5.00 P.M.

The Central Universities (Amendment) Bill, 2019

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'): माननीय उपसभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

श्री उपसभापति: क्या आप बोलना चाहते हैं।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में यह प्रावधान था...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: सर, यह सभी का आग्रह है कि यह महत्वूपर्ण बिल है, इस पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय उपयुक्त नहीं है। इसके लिए समय बढ़ाया जाए, ताकि सदस्य अपनी बात कह सकें। इस पर sense of House ली जाए। इसके लिए एक घंटा उपयुक्त नहीं है। सभी लोगों की यही राय है।...**(व्यवधान)**... जीरो ऑवर की तरह एक-एक मिनट नहीं होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय आनन्द जी।...**(व्यवधान)**... माननीय आनन्द जी।...**(व्यवधान)**... माननीय चेयरमैन ने बीएसी मीटिंग में इस पर कहा था...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: सर यह बीएसी मीटिंग नहीं है, यहां sense of House होता है।...**(व्यवधान)**...

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): सर ज़ीरो ऑवर में भी तीन मिनट मिलते हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: इस बारे में आप लोगों और सरकार के बीच बातचीत हो।...**(व्यवधान)**... आप लोगों और सरकार के बीच बातचीत हो।...**(व्यवधान)**...

डा. के. केशव राव: सर, बीएसी मीटिंग में इस पर डिस्कशन हुआ था...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: सर, हमने एक घंटा कभी नहीं माना है।...**(व्यवधान)**...

DR. K. KESHAVA RAO: In the BAC, ...*(Interruptions)*... two hours for any Bill. ...*(Interruptions)*... Then you people said ... ...*(Interruptions)*... You give three minutes in Zero Hour. ...*(Interruptions)*...

श्री आनन्द शर्मा: यह बिल एक घंटे में नहीं होगा।...**(व्यवधान)**...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, the BAC had allocated unanimously one hour.

...*(Interruptions)*... Let me finish. ...*(Interruptions)*... You can speak after that. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: LoP wants to say something. ...*(Interruptions)*...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, I agree with the hon. Members from this side that education and health are most important subjects and everybody would like to discuss it; and I suppose the Government is equally interested in education and health care. So one hour is not enough. Maybe, we might have agreed in the Business Advisory Committee but the House is more supreme than the Business Advisory Committee. So, if it has been agreed upon by the Government and the Minister also, then I personally feel that the Government should have no objection. The Government is not objecting to discussing the subject or the Bill; the Government is supporting the Bill. While supporting the Bill, why should the Government have any objection to discuss this issue threadbare? So, my submission is that minimum ' two-and-a-half hour' should be allocated for this so that the discussion is to everybody' s satisfaction. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. MURALEEDHARAN: I think, ' one-and-half-hour' is a reasonable time. ...*(Interruptions)*...

प्रो. राम गोपाल यादव: माननीय मंत्री जी, तीस मिनट में क्या हो जाएगा? इसके लिए दो घंटे होने चाहिए।...**(व्यवधान)**...

SHRI V. MURALEEDHARAN: ' Business Advisory Committee' s minutes' is there for everybody to refer. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): The House is supreme. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. MURALEEDHARAN: Whoever has participated has got that and that says ' one hour' . No objection was raised. ...*(Interruptions)*... However, since the LoP has suggested that the Members want to discuss it more, the Government is not against discussion on any Bill for the Members to express their opinion. So, ' one-and-hour-hour' is more than enough. But if somebody feels ... ...*(Interruptions)*... So, you are coming down from three to two. Okay, I agree for two. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: श्री पि. भट्टाचार्य।...**(व्यवधान)**... अभी मिनिस्टर बोल रहे हैं।...**(व्यवधान)**... सॉरी, सॉरी...**(व्यवधान)**... माननीय मंत्री जी बोलें।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': माननीय उपसभापति जी, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की 13वीं अनुसूची में यह प्रावधान था कि आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय

[श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक']

जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। श्रीमन्, इसी संदर्भ में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए 491.23 एकड़ भूमि और जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए 525.01 एकड़ भूमि की पेशकश की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया, जिसने उन सभी स्थानों का निरीक्षण करने के बाद मंत्रालय को अपनी संस्तुति दी। अनंतपुर जिले में केन्द्रीय विश्वविद्यालय और विजयनगरम जिले में जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए स्थलों का चयन हुआ। इन सिफारिशों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया और उसके बाद उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट, डीपीआर बनाने के लिए EdCIL द्वारा निर्देशित की गई और जो डीपीआर तैयार हुई, उस पर निवेश बोर्ड और व्यय-वित्त समिति ने अपनी संस्तुति दी और उसके बाद मंत्रिमंडल ने इसको स्वीकृत करने की दिशा में 16 मई, 2018 को न केवल अपनी संस्तुति दी, बल्कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ इसके पहले चरण में 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया और एक स्थायी परिसर में इस विश्वविद्यालय को शीघ्र शुरू करने का सिद्धांततः अनुमोदन दिया। केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के अनुमोदन के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 को संशोधित करने के लिए भी सदन में विधेयक पेश करने की अपनी संस्तुति दी। जहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए इस दिशा में तेज़ी से कार्यक्रम हुआ, वहीं केन्द्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की दिशा में भी 08.11.2018 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दी और आंध्र प्रदेश राज्य के वियजनगरम जिले में केन्द्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना, इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 को संशोधित करने की दिशा में संसद में विधेयक प्रस्तुत करने का भी अनुमोदन दिया और इसके पहले चरण में 420 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया।

श्रीमन्, इन दोनों Bills को लेकर संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एक केन्द्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2018 को 14.12.2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया, परन्तु इस पर विचार नहीं हो सका और इसके बाद वर्ष 2018 चला गया, अब वर्ष 2019 आया तो फिर पुनः इस पर संशोधन किया गया और मंत्रिमंडल ने फिर इस पर अपनी सहमति दी। इसको 12.02.2019 और 13.02.2019 को दो बार सूचीबद्ध किया गया, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी और 16वीं लोक सभा का विघटन हो गया। यह स्वाभाविक ही था कि जब 17वीं लोक सभा आयी, तो तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल ने 24.06.2019 को अपनी बैठक में आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय और केन्द्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, दोनों का अनुमोदन किया और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2019 को प्रस्तुत किया, अनुमोदन किया।

श्रीमन्, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि 8 जुलाई, 2019 को लोक सभा में यह प्रस्तुत हुआ और 12 जुलाई, 2019 को लोक सभा ने इसे पारित कर दिया। श्रीमन्, हम इसके लिए साथ ही साथ वित्तीय प्रावधान भी लाए, जहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय... वह जो परिसर में शुरू भी हो गया, लेकिन इसके लिए विधिवत् तरीके से केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए हम लोग विधिवत्

व्यवस्था करके लाए। केन्द्रीय विश्वविद्यालय का इसका पूरा का पूरा जो आकलन था, वह 902.07 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जबकि इसको पहले चरण में 450 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वीकृत हुआ है और केन्द्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का पहले चरण के लिए 420 करोड़ रुपये का प्रावधान है, लेकिन कुल अनुमोदन 834.83 करोड़ रुपये का हुआ है।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि बहुत कम समय में जिस तरह से केन्द्र की सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के होते ही वहां पर आईआईटी तिरुपति का निर्माण किया, इन एनआईटी का निर्माण किया, आईआईएम की स्वीकृति दी... आईआईएम की स्वीकृति दी, आईआईएमएसआर की स्वीकृति दी और आईआईआईटी की स्वीकृति दी और अब उन पांच महत्वपूर्ण संस्थानों के बाद ये दो विश्वविद्यालय, आज विचार के लिए और पारित करने के लिए हम आपके बीच लाए हैं। श्रीमान्, आज का दिन आंध्र प्रदेश के लिए एक स्वर्णिम इतिहास का दिन है। जब उसके इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ रही है। श्रीमन्, मैं बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर विचार किया जाए और बड़े खुश दिल से इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए।

The question was proposed.

DR. BANDA PRAKASH (Telangana):*

श्री उपसभापति: सिर्फ उनकी बात में रिकॉर्ड में जाएगी। डा. बांडा प्रकाश जी, आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। कृपया आप बैठ जाइए।

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, while moving the further amendment of the Central Universities Act, 2009, what has been said very clearly by the hon. Minister? He said that two Universities are coming in Andhra Pradesh. One is the Tribal University and another is the general Central University. Fair enough. I welcome it because you are going to set up a Tribal University for a particular purpose, as you have mentioned, that is, the Tribal University will promote advance knowledge by providing the institutional and research facilities in tribal art, culture, customs and advancement in technology to the tribal population in India, etc., etc. Just good enough. You have chosen Andhra Pradesh; it is fair enough. Hon. Minister, I am sure you will agree with me that in some other parts of our country such as Chhattisgarh, the concentration of tribal people is much more. You will also agree with me that in Telangana also, the tribal population is very much. In other States also such as Maharashtra, I don' t want to mention the names of all the States, you have said that there are so many places where tribal concentration is there. When you are going to set up a Tribal University, why is it in a particular State? I have no objection to setting up a Tribal University in Andhra Pradesh, but why not in Chhattisgarh where the concentration of tribal population is

*Not Recorded.

[Shri P. Bhattacharya]

much more? It is not known to me. Unfortunately, in Jharkhand, you didn' t do so. In Jharkhand and West Bengal tribal, population is quite high; it is also a maoist-concentrated area. Now, of course, it is peaceful. When your Minister including the Prime Minister visited those areas, it was a commitment made that for tribal people educational institutions will come up as a new venture. Where is it? Sir, I have gone through this Amendment Bill. In Clause 4 of the Bill, you have mentioned sixteen Universities, that is, two in Andhra Pradesh, two in Bihar, one in Gujarat, one in Haryana, one in Himachal Pradesh, two in Jammu and Kashmir, one in Jharkhand, one in Karnataka, one in Kerala, one in Odisha, one in Punjab, one in Rajasthan and one in Tamil Nadu. Visva-Bharati University is in West Bengal. Rabindranath Tagore established this University and Pandit Jawaharlal Nehru was the first Chancellor of that University. I know that Visva-Bharati University has a separate Act, but it is a Central University. Sir, in a Central University, when you have mentioned the Central University, why are you not going to complete the structure? What would be the structure, how many Vice-Chancellors in a University, and what would be the procedure, that is not clear here. That is omitted. Sir, as you know, in a Central University, as I know in Visva Bharati and other Central Universities, the Search Committee was formed and the Search Committee consisted of three or four people. Qualified educationists are there as the members of the Search Committee. They sit together and finalise two-three names and send it to the HRD Ministry and through the Ministry, send to the President of India and there, it will be finalised because the Central Universities' Vice-Chancellors will be appointed by the President of India. I have the experience. Sometimes, I have seen, though the HRD Ministry, citing a proper logic, wish to remove any Vice-Chancellor from the University, they cannot do this thing. I recall, in the case of Visva Bharati Vice-Chancellor, when I got some complaints —your predecessors were there, she was there —I raised all those complaints before this House and the investigation took place. A three-member committee was formed and the committee members then submitted the report. Even though it took six months to remove that Vice-Chancellor, that time I had requested the hon. Minister to change this Central University Act thoroughly. Sir, you were going to change, the hon. Minister is going to change Section 9, only to set up two Universities. But, the Central University Act, as a whole, is an old Act. It requires a thorough change because nowadays so many Central Universities are there and in the institutions and Universities, so many changes are taking place. So, it requires the most modern arrangements like e-education system and all those things. But, I think the hon. Minister will consider and I feel that the hon. Minister will come out very soon to change the Central Act as a whole. Sir, I have come

to know from Calcutta University, one of the best Universities in the country, that some instructions have been given through UGC to follow some of the guidelines. Why? Why is the Central Government sending some sort of instructions to the Universities and telling them, directing them to follow all these things? They should not do that thing. I am not talking about the educational policy and systems. When the hon. Minister will discuss this thing, certainly, I will raise this issue. But, today I am trying to know in regard to these two Universities, when you are going to select the Vice-Chancellor, is it true that the educational curriculum and all these things will be guided by the Central Government. Sir, all the universities have their own statutes. Who will prepare the statute? Will it be prepared by the Government of India, or, by somebody else? I don' t know which will be that organization. So, I feel that the hon. Minister should take proper action so that he can make arrangements for some independent organizations to prepare this statue.

Then, I would say that in West Bengal, Jadavpur University is one of the best universities. For a long time, we have been asking to make it a Central University. But, unfortunately, the Government of India has not done this so far. I would request the hon. Minister to look into this matter.

Lastly, these two Universities should function freely and properly without having any direction or any other pressure from the Central Government. Thank you, Sir.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): Sir, since this Bill concerns establishment of one Central University and one Central Tribal University in the State of Andhra Pradesh, and both these Universities are being set up in the State of Andhra Pradesh as per the provisions of the Andhra Pradesh State Reorganisation Act of 2014, I wish to speak in my mother tongue, Telugu. I had requested the Secretariat to arrange for the translation.

Before that, I would like to say that higher education is a very important catalyst for economic development, economic transformation, and this is also very important in building a very strong society. Before I go into the specific subject of these two Central Universities, let me go into the background.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN) *in the Chair.*]

* "After the bifurcation of the State of Andhra Pradesh in 2014, the residuary State of Andhra Pradesh now comprises thirteen districts. If we carefully observe, after

*English translation of the original speech delivered in Telugu.

[Shri G.V.L. Narasimha Rao]

Independence, the boundaries of this State and its Capital were changed on a number of occasions. I don' t think people of any other State might have experienced what people of Andhra Pradesh experienced regarding these changes. The Coastal and Rayalaseema regions were carved out of the Madras State in 1953, with Kurnool as its Capital city. Firstly, for the Seemandhra people Madras was their Capital city. Later, Kurnool became the Capital city. In 1956, the States Reorganisation Act formed Andhra Pradesh with the Telugu-speaking areas with Hyderabad as its Capital city. So, for the people of Andhra Pradesh the Capital kept changing. Initially, it was Madras, then Kurnool and later Hyderabad. In 2014, after the bifurcation of the State, people of Andhra Pradesh were again in search of their Capital city. Amaravati was selected as the State Capital and buildings were constructed on temporary basis for the same purpose. However, there is no clarity whether Amaravati will remain as the Capital city for the State of Andhra Pradesh. If we look at the problems faced by the people of Andhra Pradesh, I have no doubt in telling that, everyone will have a feeling that, not even ones' foes should face such problems. People of Andhra Pradesh are experiencing such terrible conditions. Bifurcation of Andhra Pradesh was supported by all the political parties. Bifurcation of the State did not take place because of one party. Though some regional parties started movement for the bifurcation of the State, even we desired formation of Andhra Pradesh and formation of Telangana State. The same was desired by other parties and regional parties too. Bifurcation of Andhra Pradesh was done with the support of almost all the parties. Didn' t one know earlier that the State will be bifurcated? The desire of Telangana people to have a separate State for themselves did not start all of a sudden. They had been protesting for separate Telangana State since 1969. Separate Jai Andhra Movement was initiated in 1973. When one was aware that, some day we had to separate amicably as brethren they should have worked for the development of entire Andhra Pradesh. But unfortunately that didn' t happen.

From 1956 to 1971, the United Andhra Pradesh had Chief Ministers from Andhra Pradesh region. Similarly, from 1982 to 2014, nearly for thirty two years Andhra Pradesh had Chief Ministers from Andhra Pradesh region. Sir, I fail to understand why they had not tried for balanced development or development of entire Andhra Pradesh. Few months back, I raised few questions in the Parliament. I requested for the list of National Institutions allocated for the State of Andhra Pradesh prior to bifurcation along with their location. In the reply I received, it was stated that most of the Institutions were concentrated in and around Hyderabad. The former Chief Ministers did not have a

vision. They should have thought, we are together now but we will separate amicably as brothers in future. And, if development were spread across entire Andhra Pradesh there won' t be a problem in the future. But, it did not happen this way. I am saying this because, if we see the list of Institutions established, they were all concentrated in one region. University of Hyderabad was established in Hyderabad and it was unanimous decision. Apart from School of Planning and Architecture established in the year in 2008 in Coastal Andhra, rest of the Institutes are located in and around Hyderabad. The leaders in the then Government should take responsibility for this. As development did not spread across the entire Andhra Pradesh, people feel injustice was done to them. Leaders of the previous Governments in the State should be held responsible for this. The mistakes committed by these leaders have become a curse for the people of newly formed Andhra Pradesh.

If we observe the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, in the Schedule Thirtheenth it has been mentioned that ten National Institutions should be established in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh Reorganization Act mentions that steps should be taken for the establishment of the National Institutes before the Thirteenth Five Year Plan."

The Central Government was given almost ten years to take steps for the establishment of these institutions. But because hon. Prime Minister and the Central Government are committed to the fulfillment of all the considerations, all the clauses in the Act, and we are committed to the development of Andhra Pradesh, all these institutions have been set up in the very first year after the formation of the Government under the leadership of hon. Prime Minister Narendra Modi *ji*. As per the Act, the Central Government had time till 2020-22 to start IIT and no action can be taken against the Central Government as per the Act for the delay as classes for IIT started in the year 2015-16. The Central Government thought that the State of Andhra Pradesh had faced injustice and if adequate educational opportunities are provided, it will enhance the economic development of the State. Hence, classes for IIT started during 2015-16. Classes for NIT started during 2015-16. Classes for Indian Institute of Management (IIM) also started during 2015-16 in Visakhapatnam. Classes for Indian Institute of Science Education and Research (IISER) started during 2015-16 in Tirupathi. Classes for Indian Institute of Information Technology (IIIT) started during 2015-16.

Many prestigious National Institutions such as IIT, IIM, IIIT, NIT and IISER were established in Andhra Pradesh and I think no other State received as many institutions as Andhra Pradesh received after Independence that too in such a short span of time.

[Shri G.V.L. Narasimha Rao]

I received this information in writing from Ministry of Human Resource Development. No other State in the country was allotted as many institutes as Andhra Pradesh received in such a less time. Along with this, the Central Government has started classes in Anantapur from 2018-19. Classes for Indian Institute of Petroleum and Energy started during 2016-17 in Visakhapatnam. The funds allocated to these institutes were not totally spent and it will take another one or two more years for these institutions to spend the funds towards construction and infrastructure.

The seven institutions under the Ministry of HRD include IIT, NIT, IIM, IISER, IIIT, Central University and Tribal University. The total allocation made under these institutions is ₹ 6,190 crore. * "Apart from this ₹ 1618 crores were allocated for the establishment of AIIMS" .

Allocation of ₹ 1618 crore is there for the establishment of AIIMS at Mangalagiri in Guntur district.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): This is not related to the subject.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): कृपय आप शांति बनाए रखें। ...**(व्यवधान)**...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: For Indian Institute of Petroleum and Energy, the total allocation is ₹1,056 crore and the people and the parties which have... *(Interruptions)* ...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: This is not related to the subject. ... *(Interruptions)* ...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): कृपया आप शांति बनाए रखें। जब आप अपनी बात कहें, तब आप इन बातों को कहें। ...**(व्यवधान)**...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: I will tell you that this is historic. ...*(Interruptions)*... This is historic. No Government, in the history of independent India, has ever sanctioned so many institutions and allocated so much funds. ...*(Interruptions)*... But despite this, you have political parties.....*(Interruptions)*... All this is official information. ...*(Interruptions)*... If they have a problem,**.

---

*English translation of the original speech delivered in Telugu.

**Expunged as ordered by the Chair.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाए रखें।...**(व्यवधान)**... आप चेयर की तरफ देखिए।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): आप बोलिए, लेकिन ये कैसे बोल सकते हैं। ...*(Interruptions)*... You cannot say that. ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: But, I cannot be disturbed in this manner. ...*(Interruptions)*... I have every right to speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Madam, I have a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN): Under which rule?

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: It is under Rule 258. The hon. Member, while speaking, said that if other Members do not like it, they may *. He cannot say that. So, that part should be expunged.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN): Okay. ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: I am only stating facts. These are from the replies given in Parliament. If you have a problem with this information, you can move a privilege motion against the Minister who gave these answers. All this information is authentic and official. Because you have been trying to pervade lies, people have rejected such political parties in Andhra Pradesh.

SHRI RIPUN BORA (Assam): Madam, he should stick to the Bill. ...*(Interruptions)*... He is giving all the history. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): माननीय सदस्य, कृपा करके इन्हें अपनी बात रखने दीजिए। अगर आपको आपत्ति है, तो आप अपनी स्पीच में इस बात का जिक्र कर दीजिएगा।

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Madam, all the provisions of the Andhra Pradesh Reorganisation Act as far as educational institutions are concerned have been adhered to. While there was ten years' time...*(Time-bellrings)*... Madam, please allow me some more time.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): नरसिंहा राव जी, आपको आपकी पार्टी ने पंद्रह मिनट का समय दिया है। आप कृपा करके conclude करें, क्योंकि आपकी पार्टी ने आपको केवल पंद्रह मिनट का ही समय दिया है।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Madam, we have 38 minutes. So, I think my time may please be extended because the duration has been extended. Madam, Tribal University is coming up in Vizianagaram district with a budget of ₹420 crore for the first phase. Many political parties have indulged in propaganda and have spread falsehood that the Central Government has not fulfilled its obligations. The reality is that we have given much more. We have implemented the provisions of the Act. Although we had ten years' time, we implemented this within two years.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Madam, I have a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN): Under which rule?

PROF. MANOJ KUMAR JHA: It is under Rule 240 which relates to irrelevance or repetition. Madam, we are discussing the Central Universities (Amendment) Bill. If you look at the interpretation of Rule 240, it applies very well to the hon. Member, who has been speaking about everything but the Central Universities (Amendment) Bill.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Let me inform the Member that these two institutions are being set up as part of the Andhra Pradesh Reorganisation Act.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): नरसिंहा राव जी, अगर कोई भी ऐसी बात होगी, जो इस तरह की कही गई होगी, उसको check करके expunge कर दिया जाएगा।

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Madam, you see, a lot of political parties have spread falsehood about the implementation of the Act and they feel threatened when I speak the truth about it. उनको डर लगता है, क्योंकि वे झूठ से लोगों को प्रभावित कर रहे थे। * "The parties which have deceived people by telling lies are unable to accept it when I am revealing the facts" .

People have taught lessons to the parties, which have actually propagated lies. ...*(Interruptions)*... It is high time they speak the truth; otherwise, they would suffer the consequences forever. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): नरसिंहा राव जी, आप कृपया conclude करें।

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN (Tamil Nadu): Madam, I have one point of order. ...*(Interruptions)*... It is about the use of the word ' lie' . ...*(Interruptions)*... You cannot use the word ' lie.'

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Madam, I think, even the supporting parties seem to be threatened. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: He is going on reading false. ...*(Interruptions)*...

---

*English translation of the original speech delivered in Telugu.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): नरसिंहा राव जी, आप कृपया conclude करें।

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: I am concluding, Madam. ... *(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): नरसिंहा राव जी, आपका वक्त खत्म हो गया है। आप conclude करें, वरना मैं दूसरे स्पीकर को बुला लूंगी।

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: These two Central Universities would serve as institutions of higher education and would help in the economic development of Andhra Pradesh, and what was neglected by the Governments in the State for several decades, this Government, under the hon. Prime Minister Narendra Modiji, has ensured all-round development of people of Andhra Pradesh. These institutions have come up in all the regions of Andhra Pradesh. In the Rayalaseema region, a number of them have come up. In the North Coastal Andhra area, many of them have been set up. The only area, my home district Prakasam District, was not favoured by the Governments in the State. I would request the HRD Minister. This is an important point not just for Andhra Pradesh. I think the decision of the location of the institution is being made by the State Governments. In our case, you see a concentration of institutions only in one part of the State while some regions are neglected. My appeal to the Central Government and HRD Ministry is to have a decisive say even in the location of the institution to ensure all round educational development of all the States in this country and not go by political considerations of the ruling establishments in the States concerned. Thank you, Madam.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): श्री ए. विजयकुमार। आपके पास 7 मिनट्स हैं।

SHRI A. VIJAYAKUMAR (Tamil Nadu): Madam, the Central Universities (Amendment) Bill, 2019, envisages establishment of Central University of Andhra Pradesh under Section 3C and establishment of Central Tribal University of Andhra Pradesh under Section 3D. This would enable opening of avenues of higher education and research facilities primarily for the tribal population of India. With the establishment of these two Central Universities, the total number of Central Universities in India has increased from 49 to 51. Further, under Section 5 of the Principal Act, necessary provisions have been made so that the Tribal University established under Section 3D shall take additional measures for paying special attention to the tribal-centric higher education and research, including art, culture and customs. Madam, now it is the need of the hour that more concentration is required on the Central Universities, where the research programmes are not given priority. Only through technological development and research activities, the quality of education will improve substantially and enable our students to compete at the international level. Another area of concern is the shortage of faculties and other posts in the Central Universities in India. Only when adequate faculties are posted, the

[Shri A. Vijayakumar]

students could receive quality education and push themselves for more learning through interaction and guidance. Madam, before I conclude, I would like to draw the attention of this august House that the reservation in Central institutions in all courses of studies for the locals is not a new phenomenon. Therefore, denial of reservation of 25 per cent seats in all courses in any Central University for the locals is not only against natural justice but is clearly arbitrary and discriminatory.

Such a situation should be prevailing in all the States having Central Universities in India. Madam, in this background, a demand for reservation of seats in university courses is not a concession, but a matter of moral obligation.

Therefore, I request that reservation of 25 per cent seats to local residents in Central Universities can be extended to all the 51 Central Universities in India and that would be certainly hailed as the righteous move by people everywhere.

I appeal to the Central Government to start a Tribal University in Tamil Nadu also.

Madam, I plead to arouse the collective consciousness of Members from the rest of India for realising a just demand that would satisfy the native students and youth. Certainly, the Central Government stands to get laurels from the public. A beginning can be made even with this Bill. With fond hopes, I support this bill. Thank you Sir.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Madam, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Bill. At the very outset, I would like to say that Visva-Bharati University was the first Central University to be set up in the country. It was declared by Pandit Jawaharlal Nehru on the request of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi who, in turn, was requested by *Kavi Guru* Rabindranath Tagore and since then, no second Central University has been set up in West Bengal.

I urge upon the Government to initiate appropriate steps in this regard.

Madam, I urge the Government also to ensure that Bills that are discussed in Parliament should be sent for scrutiny to Parliamentary Committees. I would like to bring up certain facts and figures. During the 14th Lok Sabha, we had seen 60 per cent of the Bills being scrutinised; during the 15th Lok Sabha, we had seen about 71 per cent of the Bills being scrutinised, and during the 16th Lok Sabha that commenced in 2014, we saw the number plummeting to deplorable 26 per cent.

Madam, I urge the Government to discuss and deliberate on Bills and not to bulldoze them through Parliament. This Bill was discussed for only 1 hour and 45 minutes in the Lok Sabha, and in this august House, after much effort by all the hon. Members, two hours have been allotted. All the 17 Bills that have been introduced in this Session, none of them has been sent to the Standing Committee for scrutiny.

Madam, this Bill aims to set up two universities. One is the Central University and the other is the Tribal University in Andhra Pradesh as a follow up to the Andhra Pradesh Reorganization Act of 2014. However, we have to look into certain harsh realities before we move to the details. We host a 33 per cent population of world' s non-literate people. Over the next few years, the country could lose about 10 crore people, nearly the population of Bihar, from the learning system in higher education.

Now, Madam, moving on to the Clauses of the Bill, the Government intends to set up a Central University in Andhra Pradesh. But what will be the administrative set-up, the programmes, the curriculum and the accreditation? The foundation of a Central University cannot be just limited to a few lines in a Bill, but it has to ensure access, equity, quality, affordability and accountability.

The Government will also establish a Tribal University in Andhra Pradesh. But has the Government held any consultations before taking this step? Tribal studies is an extensive subject and the pedagogy, curriculum, culture, practices and social customs have to be explored thoroughly before having a university dedicated to it. In phase-1 of construction of infrastructure, we have seen ₹ 450 crores for the Central University and ₹ 420 crores for the Tribal University, a total of ₹ 870 crores for two universities. For infrastructure of two Central Universities, is ₹ 870 crores enough? Will it suffice? I would like to say that the Government has always been very miser when it comes to spending on education. It is to be noted that spending on education should be ideally 6 per cent of the GDP to yield much solicited spread and access. But the share of spending on education in the whole Union Budget was 4.6 per cent in 2014-15 and, now, it has gone down to 3.5 per cent in the Interim Budget of 2019-20. I would also like to know what the Government is doing in respect of vacancies in the Central Universities. In 12 out of the 14 Central Universities, we have more than 75 per cent vacancies of Professors and two universities, most deplorably, have 100 per cent vacancies in the same post. One will always wonder about the quality of education that is being imparted there. As per the all-India Survey on Higher Education in 2017-18, the Gross Enrolment Ratio in higher education for the age group 18 to 23 is 25.8 per cent. Now we have fixed that target at 30 per cent for 2020. Even if we achieve the target, most astonishingly, 10 crore students would still not have seats at the universities. The Government, thus, has to step up funding and build infrastructure to spread and build the education system. The Government also has to speed up the process of accreditation of institutions and programmes. There are 42,000 higher educational institutions in the country. Only 20 per cent or about 8,700 institutions have been accredited by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC). There are 15,000 programmes in engineering, management, pharmacy, architecture, etc., offered by the institutions. Here too, only about 20 per cent, i.e, about 3,050 programmes have been accredited by the National

[Shri Abir Ranjan Biswas]

board of Accreditation. The Government has to conduct due diligence at the earliest and hasten the accreditation process to increase credibility of the educational system. Another very important thing that I want to bring up is, nearly, ₹ 94,000 crores collected under the secondary and higher secondary cess since 2006-07 lies unallocated and unused, according to the 2017-18 Report of the comptroller and Auditor General of India. This is most deplorable. This money needs be ploughed into the educational system to strengthen its foundation, increase access and build a student-friendly and innovative knowledge environment. Lastly, I would like to conclude by making a suggestion to the Government. The UN acclaimed Kanyashree Scheme in Bengal has now been extended for higher education as well. One time grant of ₹ 25,000 is being provided to girls who continue education after they turn 18, that is, at the under-graduation level. At the post-graduation level, the girls who are pursuing Science, are given a monthly stipend of ₹ 2,500 and those pursuing Arts, are given a monthly stipend of ₹ 2,000. This could be taken up as a national model and implemented across the country to empower women and make them equal stakeholders in our society. With this, I conclude my speech, thank you.

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं निश्चित रूप से इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं किसी भी रूप में यह नहीं मानता कि यह कोई बहुत अचम्भे का काम, जैसा अभी यहां गुणगान किया गया, किया जा रहा है।

[उपसभाध्यक्ष, (श्री भुवनेश्वर कालिता) *पीठासीन हुए]*

2009 में जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक्ट बना था, उस वक्त देश के साथ यह कमिटमेंट किया गया था कि प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय अवश्य होगा। उसी के चलते सभी राज्यों में केन्द्रीय वश्वविद्यालय कम-से-कम एक की संख्या में बनाये जाने आरंभ हुए। जब 2014 में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन का एक्ट पास हुआ, उस वक्त वह कमिटमेंट किया गया था कि आंध्र प्रदेश में एक केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय भी बनाया जायेगा। इसलिए ये दोनों commitments पुराने हैं, जो पिछले 5 साल की सरकार के समय में पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो पाए। नए मंत्री जी ने आते ही उन commitments को पूरा करने के प्रयास किया है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**... वह मैंने कह दिया कि 5 साल में पूरे हो जाने चाहिए थे। ...**(व्यवधान)**... लेकिन अब आप उन्हें पूरा कर रहे हैं, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं यहां आपसे 4-5 बातें जानना चाहता हूं, जिन्हें आप नोट कर लें और ध्यान से सुन लीजिए।

क्या आपने इन विश्वविद्यालयों के लिए जमीन का इंतजाम कर लिया है, क्योंकि आपके एक्ट के अंदर जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस संबंध में जो प्रस्तावना यहां दी गई, भाषण दिया, उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है कि आप किस स्थान पर इन विश्वविद्यालयों को स्थापित करेंगे? ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं, क्योंकि आज भी दो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं - धर्मशाला

स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय - जिनके लिए अभी तक जमीन मयस्सर नहीं हुई है। फिर आंध्र प्रदेश में दो विश्वविद्यालय बनाने के लिए आपने जमीन का क्या इंतजाम किया है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2018-19 के बजट में प्रावधान हेतु क्या वित्त मंत्रालय से आपने बात कर ली है, क्योंकि ये पुराने commitments थे। आंध्र प्रदेश सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी को शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया था, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 13 करोड़ रुपए किया गया है। वहीं जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए पहले 20 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे इस बार के बजट document में घटाकर 8 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जहां आप 850 करोड़ रुपए से इन यूनिवर्सिटीज़ को बनाएंगे - आप पहले चरण में 450 करोड़ रुपए और 420 करोड़ रुपए - उन्हें देने जा रहे हैं, लेकिन जो तत्कालीन बजट में इनके लिए प्रावधान किया गया है, वह 13 करोड़ रुपए और 8 करोड़ रुपए है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इतनी राशि से आप कोई विश्वविद्यालय तत्काल आरम्भ नहीं कर सकते। 13 करोड़ रुपए में तो गांव की एक सड़क तक नहीं बन सकती, फिर आप कैसे इंतजाम करेंगे?

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

इसके बाद, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए, जितने भी नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय बने हैं, उनके सामने...**(व्यवधान)**... माननीय सभापति जी ने भी टोका था कि सदन में आपस में बात न की जाए। ...**(व्यवधान)**... यदि मंत्री जी ही हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो उस पर आगे क्या कार्यवाही करेंगे? ...**(व्यवधान)**...

† **جناب جاوید علی خان (اتر پردیش) :** مائنے اپ سبھا ادھیکش مہودیہ، میں نشچت روپ سے اس بل کے سمرتھن میں کھڑا ہوا ہوں، لیکن میں کسی بھی روپ میں یہ نہیں مانتا کہ یہ کوئی بہت اچمبھے کا کام، جیسا ابھی یہاں گن-گان کیا گیا کیا جا رہا ہے۔

(اپ سبھا ادھیکش، شری بھوپیندر کالیتا صدر نشین ہوئے)

2009 میں جب سینٹرل یونیورسٹی کا ایکٹ بنا تھا، اس وقت دیش کے ساتھ یہ کمٹمینٹ کیا گیا تھا کہ ہر ایک راجیہ میں کم سے کم ایک کیندریہ وشوودھیالیہ ضرور ہوگا۔ اسی کے چلتے سبھی راجیوں میں کیندریہ وشوودھیالیہ کم سے کم ایک کی تعداد میں بنائے جانے شروع ہوئے۔ جب 2014 میں آندھرا پردیش کے پنرگٹھن کا ایکٹ پاس ہوا، اس وقت یہ کمٹمینٹ کیا گیا تھا کہ آندھرا پردیش میں ایک کیندریہ جن-جاتیہ وشوودھیالیہ بھی بنایا جائے گا۔ اس لئے یہ دونوں کمٹمینٹس پرانے ہیں، جو پچھلے پانچ سال ک سرکار کے وقت میں پورے ہو جانے چاہئے تھے، لیکن نہیں ہو پائے۔ نئے منتری جی نے آتے ہی ان کمٹمینٹس کو پورا کرنے کا پریاس کیا ہے، جس کے لئے میں

†Transliteration in Urdu Script.

[श्री जावेद अली खान]

انہیں بدھائی دینا چاہتا ہوں ...(مداخلت)... وہ میں نے کہہ دیا کہ پانچ سال میں پورے ہو جانے چاہئے تھے ...(مداخلت)... لیکن اب آپ انہیں پورا کر رہے ہیں، جس کے لئے آپ بدھائی کے حقدار ہیں۔ میں یہاں آپ سے چار-پانچ باتیں جاننا چاہتا ہوں، جنہیں آپ نوٹ کر لیں اور دھیان سے سن لیجئے۔

کیا آپ نے ان وشوودیالیوں کے لئے زمین کا انتظام کر لیا ہے، کیوں کہ آپ کے ایکٹ کے اندر جو اسٹیٹمینٹ دیا گیا ہے، اس سمبندھ میں جو پرستاونا یہاں دی گئی، بھاشن دیا اس میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ آپ کس استھان پر ان وشوودیالیوں کو استھاپت کریں گے؟ ایسا میں اس لئے بھی کہہ رہا ہوں، کیوں آج بھی دو یونیورسٹیز ایسی ہیں – دھرم شالہ استھت کیندریہ وشوودیالیہ اور گجرات کیندریہ وشوودیالیہ – جن کے لئے ابھی تک زمین میسر نہیں ہوئی ہے۔ پھر آندھرا پردیش میں دو وشوودیالیہ بنانے کے لئے آپ نے زمین کا کیا انتظام کیا ہے؟ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ سال 2018-19 کے بجٹ میں پراودھان ہیتو کیا وت-منترالیہ سے آپ نے بات کر لی ہے، کیوں کہ یہ پرانے کمٹمینٹس تھے۔ آندھرا پردیش سینٹرل یونیورسٹی کو شروع کرنے کے لئے دس کروڑ روپے کا فنڈ ایلوکیٹ کیا گیا تھا، جسے اس سال بڑھا کر نو کروڑ روپئے کیا گیا ہے۔ وہیں جن-جاتیہ وشوودیالیہ کے لئے پہلے تیس کروڑ روپے کا پراودھان تھا، جسے اس بار کے بجٹ ڈاکیومینٹ میں گھٹا کر آٹھ کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ جہاں آپ 850 کروڑ روپے سے ان یونیورسٹیز کو بنائیں گے – پہلے چرن میں 450 کروڑ روپے اور 420 کروڑ روپے۔ انہیں دیئے جا رہے ہیں، لیکن جو حالیہ بجٹ میں ان کے لئے پراودھان کیا گیا ہے، وہ نو کروڑ روپے اور آٹھ کروڑ روپے ہے، جو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ اتنی رقم سے آپ کوئی وشوودیالیہ تتکال شروع نہیں کر سکتے۔ نو کروڑ روپے میں تو گاؤں کی ایک سڑک تک نہیں بن سکتی، پھر آپ کیسے انتظام کریں گے؟

(شری اپ سبھا پتی صدر نشی ہوئے)

اس کے بعد، می آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وشوودھالیوں کو چلانے کے لئے، جتنے بھی نئے کیندری وشوودھالیہ بنے ہی، ان کے سامنے ...(مداخلت)... مانئے سبھا پتی جی نے بھی ٹوکا تھا کہ سدن می آپس می بات نہ کی جائے ...(مداخلت)... اگر منتری جی ہماری بات ہی نہی سنی گے، تو اس پر آگے کیا کاروائی کری گے؟]

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, कृपया इधर ध्यान दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री जावेद अली खान: जो हमारे केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, आज वे बहुत बड़े संकट से गुज़र रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें अच्छे अध्यापक नहीं मिल रहे हैं - जो 40-42 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय बने हैं। इसके पीछे कारण यह है कि वे 2009 में बने थे, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम खत्म करके, 2004 में नई पेंशन स्कीम शुरू हो गई। इन विश्वविद्यालयों के लिए ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि 2004 या 2008 के बाद जो विश्वविद्यालय बनेंगे, उनमें नई पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। अब आप नया Assistant Professor तो भर्ती कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको Professor भर्ती करना है तो किसी दूसरी University में, पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जो काम कर रहा है, उसे यहां आना पड़ेगा। इस तरह अपनी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जो काम कर रहा है, उसे यहां आना पड़ेगा। इस तरह अपनी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ छोड़कर नए विश्वविद्यालय में, जिसका आप गठन करने जो रहे हैं, कोई Professor या Associate Professor नहीं आना चाहेगा, क्योंकि वे सब 2004 से पहले भर्ती हुए हैं। इस तरह आप Assistant Professors के भरोसे कोई विश्वविद्यालय नहीं चला सकते।

एक तरीका और है - यहां IIT, IIM, NIIT की बात की गई - जब कोई नई IIT बनती है, नया IIM बनता है तो पुरानी NIIT, पुरानी IIT उसे कुछ वर्षों के लिए मेंटर करती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को आपने लावारिस छोड़ दिया है। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय आप बनाएं, उसे कुछ वर्षों के लिए पुराने केन्द्रीय विश्वविद्यालय से, पुरानी University के संबद्ध करें, associate करें, ताकि उनका वे लाभ ले सकें।

एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि जो पिछली सरकार का commitment था, आज आप एक जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में दो अलग किस्म के, अल्पसंख्यक किस्म के विश्वविद्यालय हैं। हालांकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में उनकी संख्या सिर्फ 2 है - जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी - इन दोनों का जो minority character है, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई है, वह अलग विषय है, उस पर उचित समय पर बात की जाएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हायर एजुकेशन में मुस्लिम छात्रों की संख्या सिर्फ साढ़े चार परसेंट है।

6.00 P.M.

[श्री जावेद अली खान]

अगर हम उसमें से एएमयू, जामिया और मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी, जो हैदराबाद में है, उनके छात्रों को निकाल दें, तो मैं समझता हूं कि यह तीन परसेंट से भी कम हो जाती है। ...(**व्यवधान**)...

† **جناب جاوید علی خان :** جو ہمارے کیندری وشوودھیالیہ ہیں، آج وہ بہت بڑے سنکٹ سے گزر رہے ہیں، کیوں کہ آج انہیں اچھے ادھیاپک نہیں مل رہے ہیں، جو چالیس-پینتالیس نئے کیندری وشوودھیالیہ بنے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ 2009 میں بنے تھے، جبکہ پرانی پینشن اسکیم ختم کرکے، 2004 میں نئی پینشن اسکیم شروع ہو گئی۔ ان وشوودھیالیوں کے لئے ایسا پراودھان کر دیا گیا کہ 2004 یا 2008 کے بعد جو وشوودھیالیہ بنیں گے، ان میں نئی پینشن اسکیم لاگو کی جائے گی۔ اب آپ نیا اسسٹینٹ پروفیسر تو بھرتی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پروفیسر بھرتی کرنا ہے تو کسی دوسری یونیورسٹی میں، پرانی پینشن اسکیم کے تحت جو کام کر رہا ہے، اسے یہاں آنا پڑے گا۔ اس طرح اپنی پرانی پینشن اسکیم کا لابھ چھوڑ کر نئے وشوودھیالیہ میں، جس کا آپ گٹھن کرنے جا رہے ہیں، کوئی پروفیسر یا ایسوسی-ایٹ پروفیسر نہیں آنا چاہیں گے کیوں کہ وہ سب 2004 سے پہلے کے بھرتی ہیں اس طرح آپ اسسٹینٹ پروفیسر کے بھروسے کوئی وشوودھیالیہ نہیں چلا سکتے۔

ایک طریقہ اور ہے - یہاں آئی۔آئی۔ٹی۔، آئی۔آئی۔ایم۔، این۔آئی۔آئی۔ٹی۔ کی بات کی گئی – جب کوئی نئی آئی۔آئی۔ٹی۔ بنتی ہے، نیا آئی۔آئی۔ایم۔ بنتا ہے تو پرانی این۔آئی۔آئی۔ٹی۔، پرانا آئی۔آئی۔ٹی۔ اسے کچھ سالوں کے لئے مینٹر کرتی ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں بنے کیندری وشوودھیالیوں کو آپ نے لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ میں آپ کو سجھاؤ دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی نیا کیندری وشوودھیالیہ آپ بنائیں، اسے کچھ سالوں کے لئے پرانے کیندری وشوودھیالیہ سے، پرانی یونیورسٹی سے سمبدّھ کریں، ایسوسی-ایٹ کریں، تاکہ ان کا وہ لابھ لے سکیں۔

ایک بہت اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلی سرکار کا کمٹمینٹ تھا، آج آپ ایک جن-جاتئے وشوودھیالیہ بنانے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے دیش میں دو الگ قسم کے، اقلیتی قسم کے وشوودھیالیہ ہیں۔ حالانکہ کیندری وشوودھیالیہ کی بہ نسبت ان کی تعداد صرف دو ہے – جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی – ان دونوں کا جو

†Transliteration in Urdu Script.

مائنارٹی کریکٹر ہے، جسے کورٹ میں چنوتی دی گئی ہے، وہ الگ وشئے ہے، اس پر صحیح موقع پر بات کی جائے گی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بائی ایجوکیشن میں مسلم چھاتروں کی تعداد صرف ساڑھے چار فیصد ہے۔

اگر ہم اس میں سے اے۔ایم۔ جامعہ اور مولانا آزاد اردو یونیورسٹی، جو حیدرآباد میں ہے، ان کے چھاتروں کو نکال دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین فیصد سے بھی کم ہو جاتی ہے ----(مداخلت)---]

श्री उपसभापति: जावेद जी, एक मिनट, आप **conclude** कर लीजिएगा, आपका समय खत्म हुआ, लेकिन चूंकि 6 बज चुके हैं, इसलिए माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि इस बिल पर बहस के लिए 2 घंटे के समय पर बातचीत हुई और इस पर हाउस की आम राय थी, सेंस था। इस पर हाउस सहमत हुआ और उसी ढंग से हम लोग आगे चल रहे हैं। इस बिल पर दो घंटे बहस पूरी करने के बाद आज एक और बिल है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम दोनों बिल्स, जो आज के बिज़नेस में है, उनको खत्म करेंगे। इसके लिए देर तक बैठेंगे, इस पर आम सहमति है।...**(व्यवधान)**... कृपया आप **conclude** करें।...**(व्यवधान)**...

श्री जावेद अली खान: माननीय उपसभापति जी, मैं जल्दी से अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आज साढ़े चार प्रतिशत मुस्लिम छात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। इगर इनमें से एएमयू, जामिया और मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के छात्रों की संख्या कम कर दी जाए, तो उनकी संख्या 3 परसेंट से भी कम हो जाती है। बड़ी खुशी की बात है कि हम अनुसूचित जनजाति के लोगों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के लिए यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। जब माननीय मंत्री जवाब दें, तब मैं उनसे यह उम्मीद करता हूं कि वे इस बात का भी जवाब दें कि क्या सरकार अल्पसंख्यकों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के लिए नए विश्वविद्यालय, जो अल्पसंख्यक चरित्र के हों, उसे बनाएगी? मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि अब तुष्टीकरण का ज़माना गया, अब तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने जब नया कार्यकाल संभाला, तो उन्होंने अल्पसंख्यकों के संवर्द्धन के लिए, उन्हें बहुत ज्यादा मजबूत करने के लिए आह्वान किया और आपके पीछे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बैठे हुए हैं, उन्होंने भी घोषणा की है कि हज से जो सब्सिडी बचेगी, वह अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर खर्च की जाएगी और अगले 5 सालों में 5 करोड़ स्कॉलरशिप्स अल्पसंख्यकों को दी जाएगी। इसलिए में आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अल्पसंख्यक चरित्र के नए विश्वविद्यालय, प्रधान मंत्री जी का जो **commitment** देश के साथ है, उसके साथ बनाने का कोई प्रयास या प्रावधान करेंगे?

[श्री जावेद अली खान]

सर, मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स यूनियन का बुरे तरीके से खात्मा किया जा रहा है। आपके वाइस-चांसलर्स स्टूडेंट्स यूनियन को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है इलाहाबाद का, मुख्तार भाई वहां से पढ़े हुए हैं, उस विश्वविद्यालय के अंदर 1921 से छात्र संघ का चुनाव होना शुरू हुआ था और इस देश के अंदर बहुत बड़े-बड़े नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं। आज बीएचयू में चुनाव नहीं हो रहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं हो रहा, जामिया मिलिया इस्लामिया में चुनाव नहीं हो रहा। क्या आप केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में ऐसा संशोधन करेंगे कि जिनके जरिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स यूनियन की अनिवार्यता भी निश्चित की जा सके?

[उपसभाध्यक्ष, (श्री भुवनेश्वर कालिता) *पीठासीन* हुए]

सर, आखिरी बात यह है कि आपने जो MHRD की वेबसाइट पर नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट डाला है, अभी हम लोगों के सामने तो...(**व्यवधान**)... हां, इसलिए चूंकि अब पंचायतों का इलेक्शन जनता के माध्यम से करा रहे हैं और स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन अब खत्म कर रहे हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है, उसके अंदर इस तरफ इशारा किया गया है कि पिछले दिनों में वाइस-चांसलर्स की नियुक्ति और उनकी गुणवत्ता, जो बहुत ही घटिया दर्जे की प्रक्रिया रही है, वह खराब रही है। मैं exact शब्द तो यहां नहीं कह रहा हूं, लेकिन वह संतोषजनक नहीं रही है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को निश्चित करेंगे कि आने वाले दिनों में जो भी विश्वविद्यालय बनेंगे, उसमें वाइस-चांसलर की नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और उनके पद की गुणवत्ता भी कायम रहेगी? इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

†[**جناب جاوید علی خان :** مانئے اپ سبھاپتی جی، میں جلدی سے اپنی بات سماپت کر رہا ہوں۔ آج ساڑھے چار فیصد مسلم چھاتر کیندری وشوودھیالیوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر ان میں سے اے۔ایم۔یو۔، جامعہ اور مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے چھاتروں کی تعداد کم کر دی جائے، تو ان کی تعداد تین فیصد سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ بڑی خوشی کی بات

†Transliteration in Urdu Script.

ہے کہ ہم انوسوچت جن-جاتی کے لوگوں میں شکشا کا پرچار-پرسار کرنے کے لئے یونیورسٹی بنا رہے ہیں۔ جب مانئے منتری جواب دیں، تب میں ان سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ اس بات کا بھی جواب دیں کہ کیا سرکار اقلیتوں میں شکشا کا پرچار-پرسار کرنے کے لئے نئے وشوودیالیہ ، جو اقلیت چرتر کے ہوں، اسے بنائے گی؟ میں اس بات کو اس لئے کہنا چاہتا ہوں کیوں کہ اب تشٹی-کرن کا زمانہ گیا، اب تو ہمارے پردھان منتری جی نے جب نیا کاریہ-کال سنبھالا، تو انہوں نے اقلیتوں کے سنوردھن کے لئے، انہیں بہت زیادہ مضبوط کرنے کے لئے آہوان کیا ہے اور آپ کے پیچھے اقلیتی کلیان منتری بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی گھوشنا کی ہے کہ حج سے جو سبسڈی بچے گی، وہ اقلیتوں کی شکشا پر خرچ کی جائے گی اور اگلے پانچ سالوں میں پانچ کروڑ اسکالرشپس اقلیتوں کو دی جائے گی۔ اس لئے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اقلیتی چرتر کے نئے وشوودیالیہ، پردھان منتری جی کا کمٹمینٹ دیش کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بنانے کا کوئی پریاس یا پراودھان کریں گے؟

سر، میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وشوودیالیوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈینٹس یونین کا برے طریقے سے خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کے وائس چانسلرس اسٹوڈینٹس یونین کو بالکل ختم کر رہے ہیں۔ اتر پردیش میں ایک کیندریہ وشوودیالیہ ہے الہ آباد کا، مختار بھائی وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، اس وشوودیالیہ کے اندر 1921 سے چھاتر سنگھ کا چناؤ ہونا شروع ہوا تھا اور اس دیش کے اندر بہت بڑے بڑے نیتا الہ آباد وشوودیالیہ کی چھاتر راجنیتی سے نکل کر آئے ہیں۔ آج بی.ایچ.یو. میں چناؤ نہیں ہو رہا، الہ آباد یونیورسٹی میں چناؤ نہیں ہو رہا، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں چناؤ نہیں ہو رہا۔ کیا آپ کیندریہ وشوودیالیہ ادھینیم، 2009 میں ایسا سنشودھن کریں گے کہ جس کے ذریعے یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈینٹس یونین کی انیوارئتا بھی نشچت کی جا سکے؟

(اپ سبھا ادھیکش، شری بھونیشور کالیتا صدر نشیں ہوئے)

[श्री जावेद अली खान]

سر، آخری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ایم۔ایچ۔آر۔ڈی۔ کی ویب سائٹ پر نئی ایجوکیشن پالیسی کا ڈرافٹ ڈالا ہے، ابھی ہم لوگوں کے سامنے تو ---(مداخلت)--- ہاں، اس لئے کیوں کہ اب پنچایتوں کا الیکشن جنتا کے مادھیم سے کرا رہے ہیں اور اسٹوڈینٹس یونین کا الیکشن اب ختم کر رہے ہیں، نئی ایجوکیشن پالیسی کا جو ڈرافٹ ہے، اس کے اندر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پچھلے دنوں میں وائس-چانسلرس کی تقرری اور ان کی گن-وتّا، جو بہت ہی گھٹیا درجے کی یہ پرکریا رہی ہے، وہ خراب رہی ہے، میں ایگزیکٹ شبد تو یہاں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ سنتوشجنک نہیں رہی ہے۔ کیا مانئے منتری جی اس بات کو نشچت کریں گے کہ آنے والے دنوں میں بھی جو وشوودھیالیہ بنیں گے، اس میں وائس-چانسلر کی تقرری میں پوری شفافیت برتی جائے گی اور ان کے عہدے کی گن-وتّا بھی قائم رہے گی؟ انہیں شبدوں کے ساتھ میں اس بل کا سمرتھن کرتے ہوئے اپنی بات سماپت کرتا ہوں۔]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Shri Prashanta Nanda. You have three minutes. ...*(Interruptions)*...

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, up to what time are we sitting?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Till this Bill is passed.

SHRI DEREK O' BRIEN: Who says, Sir? Who has said it? Has the sense of the House been taken? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I think,...

SHRI DEREK O' BRIEN: No, no. It has not been taken. Sir, the sense of the House has not been taken. This is not a free market where hon. Minister stands up and says, ' we will continue up to 7 pm.' No.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I think, hon. Deputy Chairman has already taken the sense of the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O' BRIEN: No, Sir. He has not taken the sense of the House. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Okay. I will look into the record. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O' BRIEN: No, no, Sir. ...*(Interruptions)*... He has asked the hon. Minister. Has any leader of the party been asked? Has any leader of the Opposition, be it Congress, Trinamool, SP or any party, been asked? ...*(Interruptions)*... Sir, one minute; one second. You are passing ninth Bill today without scrutiny! Sir, nine Bills have been passed! Not a single Bill has gone in for scrutiny. You cannot take the Opposition for granted like this. No. You will have to take the sense of the House. The hon. Deputy Chairman did not take the sense of the House. He asked the hon. Minister and the hon. Minister says that he is willing. We are not here to be counted as numbers. We want to be constructive. We want to be a constructive opposition. We have been cooperating with the Government. But, it does not mean you can take us for granted. This will be too much. Nobody has been asked. ...*(Interruptions)*...Nobody has been asked. ...*(Interruptions)*...We have been sitting here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please sit down, Mr. O' brien.

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, I did not say...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Minister, please sit down. I am saying that the sense of the House has already been taken. If it is otherwise, I will find out. Now, Mr. Minister.

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, it is wrong to attribute that my view was taken. In fact, the hon. Deputy Chairman took the sense of the House. The House said that it wanted to discuss this Bill for two hours and said that it wanted to discuss till it is over. So, he came to a conclusion. ...*(Interruptions)*...Let me finish. ...*(Interruptions)*...Let me finish. Kindly hear me. ...*(Interruptions)*...Kindly hear me. ...*(Interruptions)*... Let me finish. ...*(Interruptions)*...I am not yielding. ...*(Interruptions)*...So, when it was 6 o' clock, hon. Deputy Chairman said that today' s List of Business includes all these items. When he said about taking up of the third Bill, there was, of course, opposition from a lot of hon. Members. But, there was no opposition up to the second Bill. ...*(Interruptions)*...So, obviously, the hon. Deputy Chairman announced it. So, it is wrong to attribute that the hon. Deputy Chairman is doing at the behest of the Minister. No. We wanted it to be concluded earlier. But, everybody wanted to discuss this Bill at length. So, we have decided to discuss it for two hours and we will discuss it for one more hour. ...*(Interruptions)*...

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, let the hon. Minister not get confused. It is very simple. First, when the hon. Deputy Chairman wanted it, we asked for two hours as far as this Bill is concerned. We said that one hour will not suffice. Even the hon. Leader of the Opposition said that time for this Bill should be two hours. So, we said that the House would discuss this Bill for two hours. It does not mean that two hours will have to be taken today itself. It is two hours for the Bill. ...*(Interruptions)*...This is number one.

Secondly, Mr. Derek raised an objection as to who has taken the sense of the House. After all, we should have taken the sense of the House or approval of the House for sitting beyond 6 o' clock *i.e.,* up to 7 o' clock if the House wanted. That was not taken. So, earlier thing stands *i.e.,* we will discuss this Bill for two hours, but not necessarily today.

Thirdly, what you said is that the hon. Deputy Chairman did say that we have to take up the third Bill also to which we had opposed. We shouted and said, ' Look, the second Bill itself cannot be completed within the time. So, where is the question of imagining third Bill?' This is the question.

SHRI JAIRAM RAMESH : Sir, I am going to be in minority with my friends. We agreed that we will discuss this Bill for two hours. That was the only sense of the House. There was no sense that we will extend the time of the House. We said that we will sit for two hours to discuss this Bill. My request is: Having sat for two hours, let us sit for another half-an-hour and pass this Bill. We will finish this Bill. Let it go through. ...*(Interruptions)*... Heavens are not going to fall. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No cross-talking. Let me listen to him. Mr. O' brien.

SHRI DEREK O' BRIEN: Sir, I am not saying we should pass the Bill or don' t pass the Bill. All I am saying is that there is a certain convention. If we are agreeing, we can sit here for half-an-hour or one hour. Please understand. Sir, you look at what was said at 6 o' clock. I completely agree with Mr. Jairam. We can sit for half-an-hour. But, the issue is: You look at the proceedings. The sense of the House is to be taken from the Chair. The sense of the House was not taken. My simple request here is: The BJP, the Government has a thumping majority there and, looking at what has been happening in the last ten days, they will have majority here as

well. But, it does not mean that the opposition will concede their opposition rights. That is my limited point.

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): महोदय, यह बिल जो continuous चल रहा है, इसके लिए दो घण्टे के समय की बात हुई। नेक्स्ट बिल को आज डिसकस करने की कोई बात नहीं... आप अगर अपना कल का एजेंडा पढ़ें, इसके अंदर लिखा हुआ है, "Consideration of any business entered in the List of Business for Tuesday, July 16, 2019 and not concluded on that day" . गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कह रखा है कि हम कल डिसकस करेंगे, तो फिर हम आज के लिए क्यों insist कर रहे हैं?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): As you see, only a few speakers are left. I think, as the hon. Member has said, we are left with only a few speakers, who will be able to finish within the prescribed time. So, I think, I can take the sense of the House: Let us finish this Bill?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Okay. Now, Shri Prashanta Nanda. You have three minutes. ...*(Interruptions)*... We have given the extended time.

SHRI PRASHANTA NANDA (Odisha): Sir, this Bill is related to the Ordinance which was promulgated on 7th March, 2019. This Bill proposes to set up two Central Universities in the State of Andhra Pradesh. When the bifurcation of Andhra Pradesh took place in 2014, it was decided that one general Central University and one Tribal Central University will be given. Though five years have lapsed since then, yet I must thank the Government, especially the hon. Minister, for keeping their commitment and Andhra Pradesh has got its due. Number two, when talk about general Central Universities, which every State was awarded, including my State, Odisha, at Koraput, the motto of awarding these Central Universities is nation building. No doubt, the motto is very, very sacrosanct. A Central University at Koraput was promised in 2009. It is now 2019. Ten years have passed since. And, how the nation building is being done through that university can very well be imagined by the faculty position there. There is not a single Professor; out of twenty-three Assistant Professors, there is only one Assistant Professor; and, out of 137 teachers, there are only 17 teachers. Can such a big goal of building the nation be achieved in such a situation? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude. Your time is over. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRASHANTA NANDA: No, Sir. Please give me some more time because there were so many disturbances in the House when I started. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): But, your time is over. ...*(Interruptions)*... Your party time is over. So, please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRASHANTA NANDA: Sir, please give me just one more minute.

I want to know from the hon. Minister as to when the faculty position in the Central University, Koraput, will be adequate. I also want to know whether in other States where, generally, universities are there, their condition is the same or better. I want to know this from the hon. Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you.

SHRI PRASHANTA NANDA: Sir, now I come to Tribal Universities. This is very, very important. I am thankful to you that you have already given one Central Tribal University to Andhra Pradesh. Other Members were also saying that Odisha, Jharkhand and Chhattisgarh have tribal population. In Odisha, there are 30 districts. You go to any district, you will find tribal people there. So, those States which have got more of tribal population, they must also be given one Central Tribal University. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. The next speaker is Shrimati Kahkashan Perween.

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, मैं आज इस बिल पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। यह बिल केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में है। सरकार ने जनजातीय विश्वविद्यालय खोलकर एक बहुत बड़ा काम किया है, जिससे जनजातियों की जीवन-पद्धति, संस्कृति, परंपराओं और उनका योगदान तथा उनके जो नायक रहे हैं, उन पर अध्यापन करने का अवसर मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहती हूं कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पूरी दुनिया में नाम है। वहां रतन टाटा लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में लगभग 300 बच्चे रोज़ाना वहां अध्ययन के लिए आते हैं, लेकिन दो महीने से उस लाइब्रेरी का एसी खराब है, जिसकी वजह से लोगों का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बच्चे पठन-पाठन का काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। मैं यह इसलिए कह रही हूं, क्योंकि हम लोग विश्वविद्यालय बना रहे हैं, ताकि किसी भी... राज्य की तरक्की वहां के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही निर्भर करती है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि दिल्ली एनसीटी में चार साल

से कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने अपनी बातों में प्रोफेसरों की कमी के बारे में कहा है। हमारा यह कहना है कि देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, जिसकी गुडविल है, आज संकट के दौर से जूझ रहा है। वहां शिक्षक, छात्रों के अनुपात में नहीं है, वहां छात्रावास की कमी है, उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और एक बहुत बड़ी ताकत जो हमारी संस्थाओं को कमज़ोर करने में लगी हुई है और निजी संस्थाओं को बढ़ावा देने में लगी है, हम अगर इन सब पर ध्यान देंगे, तो हमारी जो सरकारी संस्था है, उसको डाउन करके, निजी संस्थाओं को बढ़ावा देने वाले लोगों के इरादे कमज़ोर हो जाएंगे और जो मां-बाप अपने बच्चों की अच्छी तालीम की उम्मीद रखते हैं कि वे अच्छी तालीम हासिल करेंगे और उनके अरमानों को भी पंख लगेंगे, मैं माननीय मंत्री जी से... चूंकि माननीय मंत्री जी ने यह कहा है और मैं भी उनसे एक बात यह कहना चाहती हूं कि अगर हिन्दुस्तान के नक्शे को देखा जाए, तो हिन्दुस्तान के नक्शे में बिहार वहां पर उपस्थित है, जहां इंसान का दिल होता है। आप एक साहित्यकार हैं, आप एक अच्छी कहानी लिखने वाले हैं और आपकी बहुत साहित्यिक कहानियां भी हैं। जब आपने प्रस्ताव पेश किया, तो आपने कहा कि खुश मन से इस बिल को पास करें, तो मैं उसी मन से जहां बिहार का दिल है, मैं आपको बता रही हूं कि हिन्दुस्तान के नक्शे में बिहार वहां अवस्थित है, जहां इंसान का दिल होता है। बिहार के बहुत सारे बच्चे दिल्ली पढ़ने आते हैं, तो मैं आपसे मांग करती हूं कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए और झारखंड में, चूंकि वह आदिवासी इलाका है और मेरा लगाव झारखंड से भी है, वहां जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जाए।

† **محترمہ کہکشاں پروین (بہار)**: اپ سبھا ادھیکش جی، میں آج اس بل پر بولنے کے لئے کھڑی ہوئی ہوں۔ یہ بل کیندریہ وشوودھیالیہ اور کیندریہ جن-جاتی وشوودھیالیہ کی استھاپنا کے بارے میں ہے۔ سرکار نے جن-جاتی وشوودھیالیہ کھول کر ایک بہت بڑا کام کیا ہے، جس سے جن-جاتیوں کی جیون-پدّھتی، سنسکرتی، پرمپراؤں اور ان کا گیان اور ان کے جو نائک رہے ہیں، ان پر ادھیین کرنے کا موقع ملے گا۔ میں مانئے منتری جی کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دہلی اسکول آف اکانومکس کا پوری دنیا میں نام ہے۔ وہاں رتن ٹاٹا لائبریری ہے۔ اس لائبریری میں لگ بھگ 300 بچے روزانہ وہاں ادھین کے لئے آتے ہیں، لیکن دو مہینے سے اس لائبریری کا اے-سی خراب ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی دقّتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بچے پٹھن-پاٹھن کا کام صحیح

†Transliteration in Urdu Script.

[श्रीमती कहकशां परवीन]

سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں یہ اس لئے کہہ رہی ہوں، کیوں کہ ہم لوگ وشوودھالیہ بنا رہے ہیں، تاکہ کسی بھی ... راجیہ کی ترقی وہاں کے سواستھ اور شکشا پر ہی نربھر کرتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ دہلی این۔سی۔ٹی۔ میں چار سال سے کوئی بھی تقرری نہیں ہوئی ہے۔ جیسا کے پچھلے وکتاؤں نے اپنی باتوں میں پروفیسروں کی کمی کے بارے میں کہا ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو دیش کا سرو-شریشٹھ وشوودھالیہ ہے، جس کی گڈ-ول ہے، آج سنکٹ کے دور سے جوجھ رہا ہے۔ وہاں شکشک، چھاتروں کے تناسب میں نہیں ہیں، وہاں چھاتروں کی کمی ہے، اس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے اور ایک بہت بڑی طاقت جو ہماری سنستھاؤں کو کمزور کرنے میں لگی ہوئی ہے اور نجی سنستھاؤں کی بڑھاوا دینے میں لگی ہے، ہم اگر ان سب پر دھیان دیں گے، تو ہماری جو سرکاری سنستھا ہے، اس کو ڈاؤن کرکے، نجی سنستھاؤں کو بڑھاوا دینے والے لوگوں کے ارادے کمزور ہو جائیں گے اور جو ماں-باپ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کی امید رکھتے ہیں کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کریں گے اور ان کے ارمانوں کو بھی پنکھ لگیں گے، میں مانئے منتری جی سے.... چونکہ مانئے منتری جی نے یہ کہا ہے اور میں بھی ان سے ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہندوستان کے نقشے کو دیکھا جائے، تو ہندوستان کے نقشے میں بہار وہاں پر اوستھت ہے، جہاں انسان کا دل ہوتا ہے۔ آپ ایک ساہتیہ کار ہیں، آپ ایک اچھی کہانی لکھنے والے ہیں اور آپ کی بہت ساہتیک کہانیاں بھی ہیں۔ جب آپ نے پرستاؤ پیش کیا تو آپ نے کہا کہ خوش من سے اس بل کو پاس کریں، تو میں اسی من سے جہاں بہار کا دل، میں آپ کو بتا رہی ہیں کہ ہندوستان کے نقشے میں بہار وہاں اوستھت ہے، جہاں انسان کا دل ہوتا ہے۔ بہار کے بہت سارے بچے دہلی پڑھنے آتے ہیں، تو میں آپ سے مانگ کرتی ہوں کہ پٹنہ یونیورسٹی کو کیندریہ وشوودھالیہ کا درجہ دیا جائے اور جھارکھنڈ میں، چونکہ وہ آدی-

واسی علاقہ ہے اور میرا لگاؤ جھارکھنڈ سے بھی ہے، وہاں جن-جاتھ وشوودھالیہ کھولا جائے۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you Kahkashan Perweenji; you have finished in time. The next speaker is Dr. K. Keshava Rao. You have three minutes.

DR. K. KESHAVA RAO: Why, Sir? It is increased to five. You told me because of two hours.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No. No. It is three minutes.

DR. K. KESHAVA RAO: No, No. Three minutes was increased to five. It is my submission. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA):: It was two minutes; it is increased to three minutes. ...*(Interruptions)*... That is what is written here. ...*(Interruptions)*...

DR. K. KESHAVA RAO: You expect me that I speak on it for three minutes! ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I will have to follow the time schedule. ...*(Interruptions)*... because I will have to finish it in half-an-hour. ...*(Interruptions)*...

DR. K. KESHAVA RAO: So the Chairman expected us to speak on this Bill for two minutes! ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN: My mandate is to finish it in half-an-hour. ...*(Interruptions)*... You start, at least.

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): I know, Sir, you will give me two minutes extra.

Sir, when the Minister introduced the Bill, we expected that he will speak on the content of Central University, not to give us the information that the Lok Sabha passed it two times or the Budget is so much and like that. Whatever it is, we expected him to tell us what exactly is the concept of the Central Universities as against the regular universities.

[Dr. K. Keshava Rao]

Sir, I stand to protest very strongly with all emphasis at my command against the way you have dealt with this Bill. I am for the Bill; I am for the two Universities. He says that this is fulfillment of the A.P. Reorganization Act. The A.P. Reorganization Act spoke on the same page about the Central University for Telangana. But it is not there. Your step-motherly attitude is not understood by us at all. You perhaps might be thinking that we have not given the land. I know. But we said, we have two hundred acres as far as the Central University of Hyderabad is concerned, and if you had to just give us the decision, the Central University of Hyderabad would have accommodated people there for a temporary period, and we would have adjusted the Tribal University at Adilabad. But you have not given that. Shri Narasimha Rao has spoken. Most of you people did not understand Telugu, I suppose. He just spoke what he spoke at the pre-election time. It was a poll propaganda. It was said that they have given everything to Andhra Pradesh, more than what Andhra Pradesh asked. That is what he said in poll campaign. He said at the polls it but did not get a single seat. That is the result. Now, he said that within the Plan Period, they had given many institution. But it took nearly six years, my dear, Sir, to give these two Central Universities to those people. Now, tell me, as far as the Tribal University is concerned, do you want the Tribal University to be only for tribals or anybody can join where tribal studies will be taught? This concept was being discussed, and I was a part of it, at that time when we were discussing the issue. But we did not clear it out as to what exactly we should do as far as Telangana is concerned. Now you are coming out with this Bill. That has to be given first, because jurisdictions are earmarked here. They are only for States. That means what you are giving is just Central funds, nothing more than that.

Sir, let me now go to the way the Central Universities are functioning. Sir, have you looked to your rosters? I am a member of the Senate of Hyderabad Central University. The question is, the roster is not followed, your own HRD orders wherein you are asking the Deans and other HoDs to chair when screening committee meeting takes place, screening is done as far as selections are concerned is not follolwed. That doesn' t take place. These things happen. The reservation is not honoured. There is alienation of students belonging to Harijans. You know Hyderabad Central University' s case of Vemula, of our own boy. Then there are suicides. Three suicides took place in that University. Why? What could be the reason? It is the alienation. Why is this alienation, particularly, in the Central Universities? That has to be probed into. That has to be studied. We don' t get the data as far as the research is concerned for these boys. We

don' t get the project money which you get for other universities. IIT gives you ₹ 35,000 or ₹ 40,000. In the Central University and other Universities, you don' t get it. This is what exactly is the question. The Minister must look into it and HRD Ministry must look into it. You are coming out with a new beautiful. bigger institution to manage the universities. But these issues are there with you, the reservation, the rosters, the students' alienation, and as he said, the politics among the students. How are you selecting the VCs? You look for your men and give it. Anybody who has * background gets a VC' s post! I am telling you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude.

DR. K. KESHAVA RAO: With responsibility, I am telling you. So, that it should end somewhere. I must also end the speech because time is up but, nonetheless, let me tell you, we have to have a clear concept of the Central Universities. We do have universities. This is not the first university that you are creating for us. But it should be different. It should be different either academically or administratively. So, you have to have very clear ideas as to what exactly you mean by a Central University. Again, I strongly protest one thing —you had promised an IIT and IIM and tribal university for Telangana, but you have not honoured it. I hope, at least now you would hasten the process and give us those institutions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you very much. The next speaker is Shri K. K. Ragesh. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती रूपा गांगुली (नाम-निर्देशित): सर, क्या किसी organization के नाम के बारे में इस तरह से कहा जा सकता है?...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I would check it. If there is anything unparliamentary, that would be expunged. ...*(Interruptions)*...

DR. K. KESHAVA RAO: I withdraw those words. Anyway, people would have heard it, but I withdraw those words.

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Sir, to begin with, I would request the hon. Minister to take steps to rename the proposed Tribal University as Rohit Vemula Tribal University, who succumbed to institutional murder.

Sir, while welcoming this Bill to establish two universities in the State of Andhra Pradesh, I take this opportunity to put before the hon. Minister certain pertinent issues that confront the education sector, especially higher education, in our country. As we

*Withdrawn by the Hon. Member.

[Shri K.K. Ragesh]

all know, universities are the dwelling places of ideas and idealism. They are supposed to create knowledge. They are the centres where knowledge production takes place. If we depend on private universities or foreign universities for knowledge creation, it would amount to intellectual dependence on these institutions. So, I feel it is extremely important to strengthen the public-funded university system in our country. I say this keeping the new education policy of the Government in mind.

Sir, we make a lot of rhetorical statements so far as establishment of world-class universities and institutes is concerned. How many universities in our country have got the ' world-class' tag? If you go through the QS world universities ranking and consider the top 400 universities in the world, do we have a single university that ranks within those top 400 world-class universities? No, Sir. Then, why do we make such rhetorical statements? I wish to know from the hon. Minister what efforts we are making for ensuring quality in the university education system. If you take Central Universities, you would find that 8,000 teaching posts are lying vacant, and 40 per cent of the total faculty is appointed on a temporary basis. Sir, I do not know whether any person with good academic credentials would opt for a temporary faculty position. All these things affect the quality of our university education. Again, vast majority of the students are dependent upon State Universities and affiliated colleges. What support is the UGC giving to those universities? Budgetary allocation for education, especially higher education, has been drastically reduced. The Kothari Commission had recommended that six per cent of the GDP must be spent on education. Even they had included that in their election manifesto, but what is the reality? If they want to ensure six per cent of the GDP on education, they would have to earmark, at least, 10 per cent of the Central Budget on education, but what is the status? Budgetary allocation has been drastically reduced. In 2014-15, the total budgetary expenditure was 4.1 per cent, while last year, the total expenditure was 3.17 per cent. You may be making some nominal increase, but when you take the whole budgetary allocation as a percentage, it is declining year after year.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude.

SHRI K.K. RAGESH: Just one more minute, Sir.

Sir, give me one minute more. What happened to the education cess? Right from 2014, we are collecting cess. As per the CAG Reports, ₹94,000 crore are lying unspent. This is on the basis of the CAG Report. You are imposing and collecting 3 per cent cess on education and that remains unspent, and that too at a time when our universities are

starving of funds, when the quality of education is getting deteriorated and when our university system is getting privatised as you are depending on private players and foreign players. Sir, this is not the way. You have to strengthen the public-funded university system. I am appealing to the Government to take steps for ensuring the quality education of our children by way of strengthening the public-funded education system. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Prof. Manoj Kumar Jha, you have three minutes.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Yes, Sir, I know the tragedy. Hon. Vice-Chairman, Sir,

मकतब-ए-इश्क़ का दस्तूर निराला देखा,
उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक़ याद किया।

Sir, I come from a university; I teach in a university. माननीय मंत्री जी, जैसे प्राचीन काल के राजा-महाराजाओं की कहानियां सुनते हैं, वे भेष बदलकर जाते थे और देखते थे कि प्रजा की हालत क्या है? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप विश्वविद्यालयों में जाकर कभी-कभार देख लिया कीजिए कि expansion का क्या नतीजा निकला, गुणवत्ता की क्या हालत है? वहां पर 20-20 वर्ष से लोग ad-hoc पर पढ़ा रहे हैं। तमाम तरह की आशंका, तमाम तरह की चीज़ों में है। सर, आप भेष इसलिए बदल लीजिए, क्योंकि अगर आप बिना भेष बदले जाएंगे, तो आपको सारी फाइलें गुलाबी दिखाई जाएंगी। यह मेरा पहला आपसे आग्रह है।

सर, मेरा दूसरा आग्रह इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। मैं खुद एक विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष भी रहा हूं। ओबीसी expansion हुआ, फिर हुआ, सर, 55 छात्रों के हिसाब से क्लासरूम बना हुआ है और आप 110 छात्रों को वहां पर पढ़ा रहे हैं। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो knowledge production and knowledge dissemination कैसे होगा? इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

सर, institutional discrimination के संबंध में, मैंने पहले भी सदन में कहा है। इस सदन को सामूहिक रूप से तय करना होगा, आप रोहित एक्ट इन-बिल्ट करिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ताकि institutional discrimination पर लगाम लगाई जा सके।

सर, दूसरी चीज़ यह है कि यूनिवर्सिटी में एक शुरुआती शब्द यूनिवर्स है, विश्वविद्यालय में विश्व है, तो वैश्विक दर्शन को संकीर्ण नहीं होने देना है। विश्वविद्यालयों से लड़ाई में समझ रहा हूं, कई राज्यों के अंदर यह भावना होती है कि विश्वविद्यालयों से लड़ा जाए। बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि विश्वविद्यालय, they have been in news for all the wrong reasons and not always in a right way.

[Prof. Manoj Kumar Jha]

सर, मेरा एक और आग्रह है। सर, यह lighter vein में है। जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम है, आपने इसमें 420 करोड़ लिखा है, आप या तो इसको 421 करोड़ कर दीजिए या 419 करोड़ कर दीजिए, इसमें 420 को देखकर चार सौ बीसी झलकती है। सर, मुझे एक बात और कहनी है और अभी मेरे बोलने का वक्त भी बाकी है। मेरे साथी कॉमरेड रागेश जी ने ...**(व्यवधान)**...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN: Under what rule?

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, I have a point of order. The Rule says, "You are not supposed to use offensive expressions about the conduct or proceedings of the House." ...*(Interruptions)*... What has been said just now is an offensive expression. ...*(Interruptions)*... This is beneath the dignity of this House and that must be expunged. ...*(Interruptions)*... I think this should be expunged. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN: I will look into the records. Please, carry on.

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, वे मुझसे बदला ले रहे हैं। सर, मेरे उतने वक्त को भी ध्यान में रखा जाए। रोहित के नाम से एक बात मेरे साथी रागेश जी ने कही है। सर, इस सदन में कितने लोग परिचित हैं, यह मैं नहीं जानता। सर, मख़दूम मोहिउद्दीन थे, जो आंध्र प्रदेश के, हैदराबाद के थे। निज़ाम के खिलाफ वे तेलगांना rebellion के फ्रंट में थे, जंग-ए-आज़ादी में थे और वे लेजिस्लेटर भी थे। वे कई ज़ुबानों को बहुत खूबसूरती से बोलते थे। सर, विश्वविद्यालय का नाम मख़दूम मोहिउद्दीन पर हो, जिसने जंग-ए-आज़ादी न पढ़ी हो, लेकिर बाजार का वह गाना - फिर छिड़ी रात बात फूलों की, यह मख़दूम मोहिउद्दीन का ही लिखा हुआ है। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय का नाम मख़दूम मोहिउद्दीन के नाम पर रखा जाए।

मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मैं इसके पक्ष में खड़ा हूं। आप जो संशोधन विधेयक लाए हैं, मैं इसके पक्ष में खड़ा हुआ हूं, लेकिन पक्ष में होने के बावजूद, मैं आपके समक्ष लगातार दरख्वास्त करता रहा हूं। चूंकि शिक्षक हूं, इसलिए आप ही से मेरा आमना-सामना होगा। अत: मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि विश्वविद्यालयों पर ध्यान दीजिए और तय करिए कि गुणवत्ता कैसी हो और शिक्षकों की कैसे बहाली हो। अगर आप ad hoc टीचर्स की हालत देखें, तो आपको मालूम होगा कि वे 20-20 वर्षों से ad hoc पर ही काम कर रहे हैं। ऐसे टीचरों की उम्र 50 वर्ष को पार कर गई है, लेकिन अब तक उनकी नियुक्तियां नहीं हुई हैं और अब तो उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि शायद अब उनकी नियुक्ति कभी न हो। अत: मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, जय हिन्द।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, the next speaker is Shri Swapan Dasgupta. I am sorry; you have only two minutes to speak.

SHRI SWAPAN DASGUPTA (Nominated): Thank you for this astonishing generosity, Sir. I will just make a few very quick points. The first is that we have heard people from across the Benches, demanding Central University from different States - West Bengal, Odisha, Tamil Nadu, etc. etc. Sir, the basic point which I want to address is; Do we have any conceptual clarity as to what exactly should distinguish a Central University from a State University? Education is in the Concurrent List. But, do we have that clarity in our minds? Given the nature of the problems which various Members have elaborated, I feel that there is a total confusion on this basic point. Number two, Sir, I want to refer to this question of the Tribal University. It is a very noble endeavour and the subject needs thorough research, elaboration and study. But, what is the purpose of restricting the arena of Tribal University to the whole of the State of Andhra Pradesh alone? It can be located in the State of Andhra Pradesh which is fine, but the status of that University should be national because, after all, the tribal population does extend far beyond Andhra Pradesh. Keeping in mind the spirit of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, I feel that that is something up on which the Government should act. Finally, Sir, I just want to make a point as to what universities are we striving for. And, again, here is a complete confusion. There is one type of university which seeks the pursuit of knowledge; knowledge for its own sake and, then there is another sort of university which impart skills. Some people call it a research university versus a teaching university. Unfortunately, Sir, we seem to have mixed up all these categories, with the result that today, the entire university sector is confronted with the problems which we are seeing today like lack of classrooms, lack of facilities, lack of absolute teachers, etc. The exodus goes to the private universities. Therefore, while supporting and endorsing this proposal, I do wish that the hon. HRD Minister takes it upon himself that while formulating the new education policy, which they are doing, they will take into account some of these basic fundamental questions which have unfortunately remained unanswered for very long. Thank you very much.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, the establishment of a Central University and Central Tribal University in Andhra Pradesh is an obligation under the AP Reorganisation Act which was enacted in 2014. The hon. Law Minister is just now leaving the House. I wish he would also remain present.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE; THE MINISTER OF COMMUNICATIONS; AND THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): This matter is related to the HRD Ministry, not the Law Ministry.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: It is concerned with the Law Ministry also. In fact, I have seen the Bill. The entire Bill comprises 17 lines. I really don' t understand why the Government has taken five-and-a-half years, that is, 66 months, to bring this enactment. This is my first point.

Sir, as it relates to my State of Andhra Pradesh, I am more concerned about this Bill. I have four points to be brought to the notice of the hon. Minister. First, I am talking about the Tribal University. The total cost of setting up the project, as per the Detailed Project Report, and as per the report submitted by VC, is about ₹ 950 crores. The Ministry, in the last year, and in the present Budget, together has sanctioned about ₹ 18 crores. At this rate, how many years will the Ministry take to complete the permanent campus and permanent infrastructure? I request the Minister to address this issue. The Minister has also stated that he will be completing it in two phases of two years each. Five-and-a-half years have gone, and he now says that it will take another four years. Going by the Minister's words, if ₹950 crore is sanctioned in the next year, probably, the entire process would be completed in nine years' time. This is the state of affairs so far as this issue is concerned. In the light of this background, I request the hon. Minister to fix a timeframe even for completion for this University and completion of infrastructure.

Sir, coming to the Central University, I would like to say that the Central University has been functioning. This is the second year of operation for the Central University, which is set up in Andhra Pradesh. It has no permanent campus and no permanent infrastructure. Even the academic Professors are recruited on temporary basis. So, I request that academic posts should be filled up on permanent basis, and not on temporary basis.

Sir, I would like to draw the kind attention of the hon. Minister towards the Andhra Pradesh Re-organisation Act. That is why, I wanted the hon. Law Minister also to be present. According to the hon. HRD Minister, 11 universities have been set up - IIM, AIIMS, IIIT, IIT, NIT, Central University, Tribal University, etc. None of these 11 universities has got any permanent infrastructure. None of the universities has got the permanent academic Professors. This is the pathetic state of affairs.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude now. Your time is over.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: I will just conclude. Sir, I request the hon. Minister to have a timeframe for providing permanent infrastructure for all these universities.

Apart from this, at the time of enactment of Andhra Pradesh Re-organisation Act, the then hon. Prime Minister of this country, Dr. Manmohan Singh, had promised that the Special Category Status would be granted for the residuary State of Andhra Pradesh. That is the promise which has not been fulfilled by this Government. I request the Government of India to fulfill that promise also. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Dr. L. Hanumanthaiah. You have five minutes.

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Sir, regarding the establishment of one Central University and one Tribal University in the State of Andhra Pradesh, the Minister has said, "To increase the access and quality of education of higher education and also to facilitate and promote avenues of higher education and research facilities for the people of this State." Sir, the establishment of a Central University and a Tribal University in Andhra Pradesh is a welcome step. I have two questions to ask here. You are establishing a Tribal University, whereby the tribal art, culture and customs will be preserved. Sir, it is good that you want to preserve the art, culture and customs of the tribal people but what about the life of tribal people? Will they have to stay like that only or do you wish to bring them out of their situation? Preserving the culture of any primitive people is a welcome thing but it is not good to keep them just as they have been living in their primitive stage, and, we should never do that. We should preserve their culture but what is more important is to bring them to the mainstream of the society.

Secondly, Sir, for the advancement of technology into tribal art, culture and customs, what are we doing? How do we interpret the advancement of technology into their life? By doing that, how do we bring them to the mainstream? That should be a matter of research in the Tribal University.

Sir, there are tribals across the country, not only in Andhra Pradesh. In fact, compared to other parts of the country, Andhra Pradesh has got less percentage of tribal people. I sincerely request the Government to, at least, open four tribal universities in different parts of the country, open these universities in the East, West, North and South. With the help of study and research in these four universities, you will be able to take care of the real needs of the tribal people.

Sir, there are some other important points. Sir, we talk of having a tribal university like this, a Dalit university like this, and, an upper-caste university like this, but my question is: will our universities have to work on this basis? Is it a welcome thing? I have a doubt. The Ministry of Human Resource Development has to think over this

[Dr. L. Hanumanthaiah]

point, whether even the universities have to be built on religion or caste. Sir, every university should have a research wing for tribals, dalits and other culturally important communities. ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: But the draft that you prepared... ...*(Interruptions)*...

DR. L. HANUMANTHAIAH: Just because I have done a mistake... ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You do not have to reply to him. ...*(Interruptions)*...

DR. L. HANUMANTHAIAH: No, no. My dear Rao, just because I have done a mistake... ...*(Interruptions)*... Does it mean that you have to practice it? ...*(Interruptions)*... You should not do that. ...*(Interruptions)*... You should not do that. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No cross talks please. Mr. Rao, please sit down. ...*(Interruptions)*... You don' t have to reply to him. ...*(Interruptions)*... Please be seated, Mr. Rao. ...*(Interruptions)*...

DR. L. HANUMANTHAIAH: Sir, most of the universities which have come up in the country are facing acute shortage of academic staff and infrastructure. Sir, we have hundreds of universities in the country but there is shortage of staff, ranging between 20 per cent to 80 per cent, in all the universities.

Sir, most of the universities are running on contract basis. Honorary teachers are running the universities. Is it good, Sir? Can you impart very good academic education if we have contract teachers in these universities? Sir, I request the Government to give utmost priority in appointing Professors, Lecturers and adequate staff to run the universities, which is the basic necessity for running any university.

Sir, this Government is very famous in interfering in the autonomy of the institutions and the universities. Don' t think that I am accusing the Government. At least, in the field of education, please do not destroy the autonomy of academic institutions or universities. We have seen the case of Vemula and the JNU. There are many more universities, I can make a list. Please do not allow destruction of autonomy of any constitutional institution, particularly, the academic institutions and universities.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude. Your party has two more speakers.

DR. L. HANUMANTHAIAH: I am concluding, Sir. Sir, you take any university in the country. They are not just facing shortage of teachers. But there is a lack of academic background. There is only one Indian Institute of Science which is in Bengaluru which is finding a place in the list of universities of the world. I am feeling very sorry for our universities. What is happening to our universities? Why there is lack of academic background? Is it the politics which is working there? Or is it the politics of different political parties, any political party for that matter, that has got higher ranks than the academics? Our Vice-Chancellors have to be appointed on the basis of academic credentials. They should not be appointed on organizational basis. They should not be appointed on the basis of any political leanings. They should be appointed on the basis of very clear merit. Thank you very much, Sir.

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष जी, मैं कोई बहुत विस्तृत भाषण करने की आवश्यकता नहीं समझता। हमारे इस सदन के कई सम्मानित सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी है। मैं कोई शेरो-शायरी या काव्य पंक्ति का सहारा लेने की भी जरूरत नहीं समझता, क्योंकि उससे भाषण की सुन्दरता बढ़ती होगी, मगर कोई बिन्दु हम रखते हों, शायद ऐसा नहीं होता। व्यंगात्मक बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि में इस चर्चा की गंभीरता को कम नहीं करना चाहता। इस प्रस्तावना के साथ मैं केवल bullet points के रूप में चार-पांच बातें आपके सम्मुख और आपके माध्यम से सदन के सम्मुख विचारार्थ रख रहा हूं। जो बिन्दु श्री स्वपन दासगुप्ता जी ने कहा, वह बहुत सटीक है और मैं मानता हूं कि it is high time we considered the idea of adding some brand value to a title ' Central University' .

महोदय, अब इसमें ' Central' क्या है? अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ वहां की स्थानीय राजनीति के कारण जितनी तरक्की करनी चाहिए, नहीं कर पा रही हैं, ऐसे में Central Universities उस राजनीति से कमोबेश मुक्त हैं, तो क्या Central Universities अपनी एक नई पहचान बना सकती हैं? क्या एक brand-building हो सकती है? इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, जो textbooks वहां पढ़ाई जाती हैं, क्या उनमें कोई गुणात्मक अंतर है? क्या इसके बार में भी कोई कोशिश हुई है? क्या हमने इसका कोई आकलन बनया है?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जितनी Central Universities बनी हैं, इनका एक बार institutional audit होना चाहिए। हम financial audit तो करते हैं, कभी-कभार CAG thematic audit भी करता है, मगर जो institutional life है, उसका ऑडिट नहीं हो पाता है। आज समस्या यह है कि वहां जितने संवैधानिक परिमंडल काम करते हैं, जो बॉडीज़ काम करती हैं, चाहे Senate हो, Management Council हो, Academic Council हो, इनके अंदर किस पद्धति का काम चलता है, हम यह नहीं जानते हैं। जो लोग आते हैं, वे कितने दायित्व भाव से वहां पर काम करते हैं? उसके अंदर से जो निकलता है, वह किस पद्धति का निकलता है? मैं मानता हूं कि इसका एक संस्थात्मक लेखा परीक्षक, एक institutional audit होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

[डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे]

महोदय, यहां पर Tribal Universities के बारे में चर्चा हुई। यह बात सही है कि अमरकंटक में Indira Gandhi National Tribal University बरसों से काम कर रही है। उपयुक्त होगा कि अगर उस यूनिवर्सिटी के अनुभव के आधार पर उसका भी कोई एक institutional audit हो और उससे जो भी lessons हम सीख पाते हैं, उसके आधार पर इसके बारे में एक नई रचना बनाई जाए। वैसे हमारे जो tribal communities के लोग हैं, हमारा जो जनजातीय समुदाय है, उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं आती हैं। उनकी जो खेती करने की पद्धति है, वह बहुत प्राचीन है। भारत में कई लोग jhum cultivation करते हैं, उसके लाभ-हानि के बारे में और नये ज़माने में एक नये परिप्रेक्ष्य में उसकी भी चर्चा होनी चाहिए।

Tribal communities के बारे में कई sociological issues हैं, inter-tribal communities भी हैं, कहीं न कहीं इसके अध्ययन की, चर्चा की और कुछ सोच बनने की ज़रूरत है। अगर ये काम Tribal Universities करती हैं, तो वाकई में उनका कुछ न कुछ उपयोग होगा, ऐसा मुझे लगता है।

मुझे एक और चीज़ भी लगती है, जहां तक Central Universities की बात है, जैसा मैंने कहा कि Central Universities में हमें शिक्षा के, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये प्रयोग करने की जरूरत है। घिसे-पिटे रास्तों से ही हम चल रहे हैं। मैं मानता हूं कि नया ज़माना, new India अब इस घिसे-पिटे रास्तों से त्रस्त हो चुका है। अब कुछ नया होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम Arts, Science and Commerce की बात करते हैं। ज्यादातर बेरोज़गारी की समस्या इन तीन faculties के संदर्भ में आती है। Management और Engineering के छात्र तो कहीं न कहीं जॉब ले जाते हैं, मगर Arts, Science and Commerce वालों को जॉब नहीं मिलती। तो इनक जो six semesters का पाठ्यक्रम होता है, क्या इसको five semesters में पूरा करते हुए, एक पूरा semester हम experience and exposure-based learning को नहीं दे सकते? अगर ऐसा होता है, तो इनकी नौकरी पाने की क्षमता बढ़ेगी। आज हम देखते हैं कि कोई इंग्लिश विषय में ग्रेजुएट होता है, तो BA with English Literature can' t even write a full paragraph in English without committing any mistake. इस विडम्बना को दूर करना है, इसे हमें ही दूर करना है। यह कोई आसमान से आकर करेगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए इसका प्रयोग करने के लिए हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। विदेश में हमारे कई वाइस चांसलर्स जाते हैं, इस सदन के सदस्य भी जाते हैं और देखते हैं कि विदेश के विश्वविद्यालयों में जो मेधावी छात्र होते हैं, उनको रिसर्च असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट के जॉब्स मिल जाते हैं। क्यों नहीं यह हमारे यहां भी होना चाहिए? हमारे छात्रों के लिए earn while you learn के माध्यम से teach while you learn भी तो हो सकता है। सीनियर क्लास का कोई छात्र जूनियर क्लास के छात्रों को कुछ मात्रा में पढ़ाने की हिम्मत या क्षमता क्यों नहीं रखता, वह जरूर रखता है। ऐसे अवसर देने की दिशा में कोई pro-active विचार होना चाहिए। वह ट्राइबल यूनिवर्सिटी या सेंटल यूनिवर्सिटी हो, मैं मानता हूं कि ये ऐसा कर सकते हैं। वही विषय छात्रों की सहभागिता का है। विश्वविद्यालयों के प्रबंधन

में छात्रों की सहभागिता कोई केवल सिम्बॉलिक विषय नहीं है। इसे छात्र अच्छे तरीके से समझते हैं। क्यों न छात्रों को ही कहा जाए कि वे टेक्स्ट बुक बनायें। हम पाठ्यक्रम बनाने में उनकी मदद लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि छात्र इसमें अधिक अच्छा योगदान दे पायेंगे। बहुत वर्षों से पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले जो प्राध्यापक हैं, तो शायद छात्र उसमें और अधिक एक प्रासंगिक वैल्यू जोड़ सकेंगे। इसके बारे में भी विचार होना चाहिए।

महोदय, एक और महत्वपूर्ण बिन्दु है। जैसे हम देखते हैं कि कई विश्वविद्यालयों के द्वारा affiliated management institutions होते हैं। मैं मुम्बई से आता हूं and there is a Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies. It is a very renowned management institution. But, unfortunately, the management of the Jamnalal Bajaj Institute is in shambles. यह कौन सी विडम्बना है? हम जो प्रबंधन विज्ञान के इतने बड़े-बड़े संस्थान चलाते हैं, उन संस्थानों का, उन विश्वविद्यालयों का जो प्रबंधन है, वह बहुत ही शोचनीय स्थिति में है, बहुत ही दुखद स्थिति में है। इसलिए यह जो विश्वविद्यालयों के प्रबंधन की बात आती है, तो कई बार मुझे लगता है कि कॉलेजेज़ में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जो non-teaching staff होता है, शायद हमने मान लिया कि वह non-learning staff है। ऐसा नहीं है, जो उनको भी तो पढ़ाओ, उनकी भी तो क्षमता का विकास करो। क्यों न ऐसे नये विश्वविद्यालयों में हम business administration का, management का एक degree course चलायें, जो school administration की बात करे, जो college administration की बात करे और जो university administration की बात करे। वर्षों से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको roster तैयार करना नहीं आता, वर्षों से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको pay sheet बनाना नहीं आता। मैं मानता हूं कि इस अवस्था में अगर किसी का दायित्व है, तो हम सब का है। इसमें सुधारों की जरूरत है, नयी सोच की आवश्यकता है।

वाइस चांसलर्स की भी यही स्थिति है। अच्छे विद्वान व्यक्ति वाइस चांसलर्स होते हैं। यह बड़े ही सम्मान की बात है। मैं शीश झुकाकर उनको नमन करूंगा, मगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनका तनिक सम्बन्ध नहीं होता। इसलिए इतना विद्वान व्यक्ति अब कुलगुरु हो जाता है, कुलपति हो जाता है, तो प्रबंधन विज्ञान के साथ उसका कोई परिचय न होने के कारण उसकी विद्वता एक जगह और प्रबंधन की स्थिति दूसरी जगह हो जाती है। मैं मानता हूं कि इसके बारे में वाइस चांसलर्स की भी एक structured training होने की जरूरत है। इसके चलते हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जो संस्थात्मक मूल्य है, उसको बढ़ाने की दिशा में हम काम कर पायेंगे।

महोदय, मैं दो अन्तिम बिन्दु कह कर अपनी बात को विराम दूंगा। हम देखते हैं कि इस सरकार ने कई जगह एक स्पर्धात्मक दृष्टि का बहाव लाया है। Districts को compete करने के लिए कहा जाता है, उसके आधार पर "स्वच्छ भारत" के बारे में शहरों का चयन होता है। क्यों न हम यूनिवर्सिटीज़ के अन्दर भी एक स्वस्थ और प्रगतिशील तरीके की competitive spirit का निर्माण करें। इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, why can' t the Government declare the best Central University every year, the best Vice-Chancellor every year and the best Teaching Department every year? ऐसा कुछ करोगे, तो वहां कुछ जान आयेगी, नहीं तो पगार

[डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे]

7.00 P.M.

तो एक जगह से आती ही है, छात्र पढ़ें या न पढ़ें, बैठें या न बैठें, काम तो वैसे ही चल रहा है। मैं मानता हूं कि यह जो यथास्थितिवाद है, यह जो status-quoism है, इसको हमें और हिलाना होगा, इसको समाप्त करना होगा। नया भारत कुछेक नयी सोच की उम्मीद रखता है। मैं मानता हूं कि यह जो नया विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, वह कहीं भी बने, चाहे आंध्र प्रदेश में बने या देश में अन्य कहीं बने, इस नयी सोच का परिष्करण करने के लिए सामने आये।

मैं अब अन्तिम बात कहूंगा। हमारे इस समय के बजट में विदेशी छात्रों के बारे में एक बात कही गयी है कि अच्छी संख्या में विदेशी छात्र हमारे देश में आये। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि पूरे विश्व में भारत 26वां destination country है। हम 26वें क्रमांक में आते हैं, जहां विदेशों से हमारे देश में छात्र आते हैं और अगर source country का हिसाब लगायें, तो India is the third source country, जहां से विदेशों में छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं। क्या इस अवस्था के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए? यह जो 26वां नम्बर है, हम कम-से-कम 10वें नम्बर पर या 15वें नम्बर पर आयें, इसके लिए हम सब को मिकर कोशिश करनी पड़ेगी। इस बात का कोई आंकड़ा मेरे ख्याल से आधिकारिक तौर पर नहीं आता, मगर मेरी जानकारी है कि आज हमारे देश में एक लाख से भी अधिक विदेशी छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। मगर आज तक इनका कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है कि वे किस पद्धति से सोचते हैं। अफगानिस्तान से हमारे यहां छात्र आते हैं। वे कई बार शादीशुदा होते हैं। उनकी एक रचना होती है। मतलब उनके लिए जरूरी होता है कि यहां पर उन्हें कोई घर मिले, अच्छी पद्धति की रचना मिले, hostels मिलें।

इन सब चीज़ों पर कौन ध्यान देगा? मैं बताना चाहता हूं कि पड़ोसी देशों में हमारे देश से पढ़कर गए हुए कितने छात्र ऐसे हैं, जिनमें से कोई आज बंगला देश का प्राइम मिनिस्टर है, कोई नेपाल में किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठा है, कोई अफगानिस्तान का Foreign Minister है। यह हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है, जो हमारी soft power है। इस दृष्टि से भी, नए विश्वविद्यालयों के बारे में सोचते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।

महोदय, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों की बातें हमने कहीं। ह्वेनसांग और फाह्यान इस देश में आए, उनकी कहानियां भी हमने इतिहास में पढ़ीं। आज से 100 साल बाद, यदि कोई हमारा इतिहास पढ़े, उसे बताने लायक हमारे यहां विश्वविद्यालय होने चाहिए, वैसे छात्र यहां आने चाहिए। मैं मानता हूं कि इस दिशा में कुछ सार्थक कदम नई शिक्षा-नीति में उठाए गए हैं, जिसे लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। मैं सरकार को बधाई देता चाहूंगा कि नई शिक्षा-नीति, इतने लम्बे अंतराल के बाद भले ही आई है, मगर सरकार ने एक political will दिखाते हुए, नई शिक्षा नीति को उजागर किया है। उसे अमल में लाने के लिए, पूरी ताकत जुटाते हुए, देश में एक नया मन्वंतर हो, इसकी चिन्ता हम करें, नए भारत के अनुरूप, नई विश्वविद्यालयीन व्यवस्था का

शिलान्यास करें, इन्हीं शब्दों के साथ सदन में प्रस्तुत बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. The next speaker is Shri Kanakamedala Ravindra Kumar. You have three minutes.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, this is an issue related to our State. I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion. The Bill is meant for formation of a Central University and a Central Tribal University in Andhra Pradesh. Section 3C and Section 3D respectively have to be included by amending the Act. In fact, a Central University has already been functioning under temporary sheds. No permanent faculty is there. Guest faculty are there. There are no permanent structures. Now, it has been running with a few students without any infrastructural facilities.

Sir, as far as Tribal University is concerned, the hon. HRD Minister has given a reply to a Starred Question before this House on 11th. The Union Cabinet has already approved the proposal of establishment of a Central Tribal University in the State of Andhra Pradesh with the provision of funds of ₹ 420 crores for meeting the first phase expenditure towards establishment of Central Tribal University. Already, the AP Re-organization Act was enacted in the year 2014. More than five-and-a-half years have completed. I am thankful to the hon. HRD Minister for introducing this Bill, at least, now before this House. The only pity is that only ₹ 18 crores have been released for this purpose. The total expenditure is ₹ 950 crores. How many years would it take to construct permanent buildings and infrastructural arrangements? Likewise, there are eleven educational institutions as per the 13th Schedule of the A.P. Re-organization Act. It is not the mercy of any other. By virtue of the division, the Andhra Pradesh has sustained huge loss and the A.P. Re-organization Act has mandated a provision to constitute Central institutes. A total of more than ₹ 13,500 crores have to be released for that purpose. About ₹ 638 crores have been released. Remaining more than ₹ 12,900 crores have to be released for establishment of institutes specified under Thirteenth Schedule. If that is so, how many long years will it take? So, merely introduction of a Bill is not sufficient. Therefore, through you, I would request the hon. Minister to take care of all educational institutions under Thirteenth Schedule of A.P. Re-organization Act, to sanction the required funds and also to see that buildings are constructed. The Andhra Pradesh Government has already allocated ₹ 525 acres in Relli Village in Vizianagaram District long back. A compound wall has also been constructed. No steps have been taken so far. So, the dreams of the Andhra people did not come to reality

[Shri Kanakamedala Ravindra Kumar]

till now even after six years. I request the hon. Minister to take a special care with regard to not only Tribal University and Central University but also the other educational institutions as per the Andhra Pradesh Reorganization Act.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude. Your time is up.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, I would like to mention one more issue. There is another village. Now, the present Government wants us shift the present university from one place to another place. I do not know the particulars of that. But, the Selection Committee has already inspected and it has already got approval. I would request the hon. Minister to take steps to construct the University at Relli Village of Vizianagaram District which was already approved by it. Thank you, Sir.

श्री प्रदीप टम्टा (उत्तराखंड): महोदय, मुझे आपने इस बिल पर बोलने की अनुमति दी, मैं आपका आभारी हूं। मैं इस बिल के समर्थन में हूं, यह पुराना commitment है Andhra Pradesh Reorganization Act के अनुसार, लेकिन मैं अपनी कुछ बातें इस पर जरूर कहना चाहूंगा। इस बिल की प्रस्तावना में जो मूल उद्देश्य बताया गया है, वह इस प्रकार से है, "भारत की जनजातीय जनसंख्या के लिए प्राथमिक रूप से उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के अवसर प्रदान करने के लिए, आंध्र प्रदेश राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी", बाकी है कला, संस्कृति और रुढ़ियों... लेकिन इस बिल का चरित्र कहीं यह नहीं बताता है कि किस तरह से देश के और आंध्र प्रदेश के जनजातीय लोगों को वहां समायोजित किया जाएगा? उसमें प्रवेश के लिए जो admission का structure है, क्या वह जो मान्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का है, वही रहेगा? जो फैकल्टी का स्ट्रक्चर है, क्या वह वही रहेगा? अगर कोई बुनियादी अंतर नहीं है, तो ट्राइबल विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों में क्या अंतर है? आप जो घोषित लक्ष्य लेकर आए हैं कि भारत की जनजातीय जनसंख्या के लिए प्राथमिक रूप से उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के अवसर प्रदान करने के लिए... यह character, यह उद्देश्य इस बिल में कहीं परिलक्षित नहीं है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस विश्वविद्यालय एक्ट में किस तरह के नियम बनाए हैं, जिससे इसका चरित्र देश के जनजातीय लोगों को पूरी तरह से दिखे? अगर अन्य विश्वविद्यालयों का जो character है, वही character इसका भी रहेगा, तो हम इसको ट्राइबल यूनिवर्सिटी किस रूप में कह पाएंगे? इसके दो उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य यह है कि ट्राइबल्स के कल्चर का अनुसंधान करना एवं उनसे संबंधित तमाम चीज़ों पर रिसर्च करना और एक पुराना उद्देश्य है कि ट्राइबल लोगों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अवसर प्रदान करना, आप इस प्रथम उद्देश्य को कैसे पूरा करेंगे?

आप केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के एक छोटे-से सूत्र में परिवर्तन के लिए आए हैं, लेकिन आज जिस तरह से देश और दुनिया बढ़ रही है, देश की सरकार कह रही है कि

हम दुनिया के लोगों को भी अब इस देश में हायर शिक्षा के लिए लाएंगे, इसके लिए पूरे केन्द्रीय विश्वविद्यालय एक्ट में, हमारे concept में बदलाव की जरूरत है। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें faculties पूरी नहीं हैं, सभी जगह लगभग 60 परसेंट faculties ही भरी हुई हैं। एक तरफ तो आप ट्राइबल्स को उच्च शिक्षा में अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ट्राइबल विश्वविद्यालय से संबंधित बिल लेकर आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज देश में जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकांश पद खाली पड़े हुए हैं, जिसके बारे में आप खुद जानते हैं। मैं तीन-चार केन्द्रीय विश्वविद्यालय के आंकड़े देना चाहता हूं। यह हमारे पास उसका प्रिंट है, उसके सोर्स में मैं बता रहा हूं कि विश्वविद्यालयों की faculty positions में एससी, एसटी की क्या हालत है। सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 98.36 परसेंट पोस्ट्स खाली हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 93.1 परसेंट पोस्ट्स खाली हैं। ये अपर पोस्ट्स हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 75 परसेंट पोस्ट्स खाली हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 74 परसेंट पोस्ट्स खाली हैं। हमें इस संदर्भ में भी सोचने की जरूरत है। आज यह देश का सबसे वंचित समुदाय है। आज एससी, एसटी, ओबीसी की क्या स्थिति है? सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एससी छात्रों की संख्या साढ़े बाहर परसेंट है। एसटी छात्रों की संख्या साढ़े चार परसेंट हैं। ओबीसी छात्रों की संख्या 33-34 परसेंट के बीच में है। Minorities साढ़े चार-पांच परसेंट के बीच है। यह वंचित तबका कहीं न कहीं विक्टिम है। ये समाज के marginalised sections हैं। इनके enrolment को बढ़ाने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, इस पर भी सोचना चाहिए। जब तक इस संदर्भ में नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सर, मैं ट्राइबल यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में हूं। हमारे एक माननीय सांसद ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय में कोई अंतर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय एक ब्रांड नेम है। मैं यह नहीं मानता हूं कि इनमें कोई अंतर नहं है। हम उसका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। आखिर हर राज्य अपने यहां एक एम्स को स्थापित करने की कोशिश क्यों कर रहा है? सर, एम्स ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में एक मापदंड स्थापित किया है। वैसे ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने भी स्थापित किया है...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): प्रदीप टम्टा जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री प्रदीप टम्टा: सर, मैं समाप्त करता हूं। सर, लेकिन हमें राज्य के विश्वविद्यालयों की स्थिति के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आज हायर एजुकेशन के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का कारवां बढ़ता चला जा रहा है। इस देश के लगभग 45 परसेंट बच्चे निजी संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेज़ में जा रहे हैं। वहां स्टडी मात्र मैनेजमेंट की हो रही है, जो फाइन आर्ट्स है, Social Science आदि विषयों के अध्ययन या जो नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय नॉलेज के पावर सेंटर्स हैं, फिर भी उनमें social science आदि का अध्ययन नहीं हो रहा है। ऐसे में आप उस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रभाव को कैसे रोकेंगे?...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप समाप्त करें। अभी एक और वक्ता हैं।

श्री प्रदीप टम्टा: सर, मैं समाप्त कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी, जहां से आप आते हैं - वहां के विश्वविद्यालयों तथा - आज हमारे देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं में faculties की कमी है, टीचर्स नहीं हैं और अभी माननीय सदस्य ने बताया कि लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं है। सर, पिथौरागढ़ क्षेत्र में एक आंदोलन चला है, खूबसूरत आंदोलन है, "पुस्तकें दो और टीचर्स दो"। अगर विश्वविद्यालयों और कॉलेजेज़ में पुस्तकें और लाइब्रेरी ठीक नहीं होगी, पुस्तकें आज के आधुनिक स्तर की नहीं होंगी, टीचर्स नहीं होंगे, तो बच्चे विश्वविद्यालय में क्या पढ़ेंगे?

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): धन्यवाद। अभी दूसरे स्पीकर्स भी हैं।

श्री प्रदीप टम्टा: सर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं सिर्फ तीस सेकंड्स लूंगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आपने एक विशेष समस्या के लिए, विशेष जनों के लिए, वंचित वर्ग के लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी दी है, वैसे ही हमारा जो हिमालयन क्षेत्र है, उसकी भी कुछ अलग जरूरतें हैं। जहां आप देश के विभिन्न राज्यों में भौगोलिक आधार पर विश्वविद्यालय खोल सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में आपने जम्मू रीजन के लिए और कश्मीर रीजन के लिए दो अलग-अलग विश्वविद्यालय दिए हैं, बिहार में आपने उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में दो अलग-अलग विश्वविद्यालय दिए हैं, तो हमारे उत्तराखंड राज्य में भी कुमाऊं डिविज़न में एक अलग विश्वविद्यालय दीजिए। इसके लिए पिथौरागढ़ में आंदोलन चल रहा है, आप उस ओर भी देखें। जय हिन्द, जय भारत।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Next speaker is Shri Sushil Kumar Gupta.

श्री सुशील कुमार गुप्ता: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने आंध्र प्रदेश में एक जनरल यूनिवर्सिटी और एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए क्रमश: 450 और 420 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। मुझे खुशी है कि आप देश में पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से ट्राइबल पॉपुलेशन के कल्चर को जानने का अवसर प्राप्त होगा और भविष्य में आने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सुनहरा अवसर होगा। परंतु मेरा आपसे निवेदन है कि जो हमारी existing universities हैं, उन्हें बेहतर तरीके से संभाला जाए।

सर, यूजीसी के अनुसार इस देश में कुल 874 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें से 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 391 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 125 deemed universities हैं और 311 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 17,092 टीचिंग स्टाफ है, जिनमें से teaching faculty में 35 परसेंट सीट्स खाली हैं। अगर मैं ad hoc faculties को मिलाकर बात करता हूं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 47 परसेंट सीट्स खाली हैं, जेएनयू में 34 परसेंट सीट्स खाली हैं, Haryana Central University में 76 परसेंट सीट्स खाली हैं, इलाहाबाद में 67 परसेंट, हिमाचल प्रदेश में 60 परसेंट और ओडिशा में तो हद हो गई है, वहां 88 परसेंट सीट्स खाली हैं। कुल 60 परसेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास आधारभूत infrastructure का अभाव है। अगर हम देश के भविष्य को faculties के अभाव में, मूलभूत

ढांचे के अभाव में, लाइब्रेरीज़ के अभाव में बैठाकर रखेंगे, तो भारत के बेहतर भविष्य की कल्पना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोठारी कमीशन ने वर्ष 1964 में education sector में हिन्दुस्तान में जीडीपी का 6 परसेंट देने का सुझाव दिया था। वर्ष 2014-15 में हम जीडीपी का 4-6 परसेंट खर्च करने में लगे थे, परन्तु धीरे-धीरे, घटते-घटते अब 3.4 परसेंट रह गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कटऑफ 99 परसेंट तक जाने लगी है, इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा न होने की वजह से दिल्ली के बच्चों को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और देश के अन्य भागों में एडमिशन लेने की लिए जाना पड़ता है। मेरा एच.आर.डी. मिनिस्टर जी से निवेदन है कि आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी बनाएं, परन्तु दिल्ली के अंदर भी सीटें बढ़ाने का प्रावधान करें। आप self-finance scheme के द्वारा दिल्ली के अंदर सीटें बढ़ा सकते हैं। दिल्ली के अंदर भूमि की कमी है, दिल्ली के वर्तमान इन्फ्रास्ट्रक्चर को अधिक बढ़ाने के लिए डीडीए भूमि उपलब्ध नहीं कराती, यहां पर माननीय यूडी मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्मम से माननीय यूडी मिनिस्टर से भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली के स्कूलों का लैण्ड यूज़ चेंज करके उनका educational land use दिया जाए, ताकि सुबह की शिफ्ट में स्कूल चले और शाम की शिफ्ट में कॉलेज चले और दिल्ली के बच्चों को देश और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में न जाना पड़े, अपितु देश और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के बच्चे दिल्ली के अंदर आएं और दिल्ली की शान बढ़े, हिन्दुस्तान की शान बढ़े और हिन्दुस्तान के अंदर foreign currency आ सके।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और अनेक अन्य कॉलेज अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं, परन्तु डीडीए द्वारा भूमि नहीं दी जाती, जिससे यहां पर बहुत दिक्कत होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली और देश और पूरी दुनिया, जब हम विश्वविद्यालय का निर्माण करते हैं, तब उसकी तरफ देखता है। आज हिन्दुस्तान के विश्वविद्यालयों का नम्बर दुनिया में बहुत नीची category में आता है। अगर हम विश्वविद्यालयों की रैंकिंग देखते हैं, तो हमारे बच्चे भी दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंदर जिनकी रैंकिंग अच्छी है, वहां जाना पसन्द करते हैं, अगर हम अपनी faculty को पूरा करेंगे, ad-hoc faculty की बजाय permanent faculty देंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि दुनिया के अंदर हिन्दुस्तान के विश्वविद्यालयों के बेहतर रैंकिंग होगी और हिन्दुस्तान के विश्वविद्यालयों में दुनिया के बच्चे आना पसन्द करेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): धन्यवाद, आप conclude कीजिए।

श्री सुशील कुमार गुप्ता: महोदय, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप जहां पर हिन्दुस्तान के विश्वविद्यालयों को सुधारने का प्रयत्न करेंगे, वहीं दिल्ली के लाखों बच्चों को प्रतिवर्ष हिन्दुस्तान के अलग-अलग कोनों में जो जाना पड़ता है, आप यहां पर भूमि उपलब्ध कराएं, ताकि यहां पर भी हायर एजुकेशन बढ़ सके, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Shri Syed Nasir Hussain. Mr. Hussain, is it your maiden speech?

SHRI SYED NASIR HUSSAIN (Karnataka): No, Sir. It is not my maiden speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): All right. You have five minutes.

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak today. I have prepared so much that I would have needed, at least, 20-25 minutes to make all the points. Many speakers before me, including my own party colleagues, have raised many issues, and have spoken about many things which I wanted to raise. I would just like to restrict myself to two, three points, for which I think, I have three, four minutes. It is actually good to see that the Government is honouring the promise that was made to the people of Andhra Pradesh in the Andhra Pradesh Reorganization Act of 2014. It is also good to know that the present Government is not only honouring the promise that was made by the previous Government, but, at the same time, this Government is also thinking of expanding the higher education. Several points have been made by several Members here. But, I would like to refer specifically to the points made by the BJP Member from Andhra Pradesh. He was speaking so much about the achievements of the Modi Government in the last five years. I need to remind the Members in the Treasury Benches. I would like to give some data here and especially to the friend who was speaking about Modi Government and its achievement in the past five years. As of 2017-18, 1,20,769 Assistant Professors and 45,148 temporary teacher positions have not been filled. Over 2,07,000 teaching positions are vacant at all levels. This is the track record of the Government. We can speak about the new universities, we can start new universities, we can start new institutes of higher education, but if we don' t have faculty positions filled, if we don' t have new professors coming over, I think it will be a sheer waste of money and the Government should, while starting new universities, concentrate on filling up not only the positions, but also trying to attract some of the best brains from different parts of the world. We have our own people working in different universities across the world. Probably the reason here is, the kind of freedom and autonomy, which is necessary for a university functioning, is not there. That is the reason some of our best friends are still teaching abroad. Someone here was speaking about attracting students from abroad and this was also mentioned in the Budget Speech. I would like to mention it here. मुझे लगता है कि अभी-अभी महाराष्ट्र से सदस्य बात कर रहे थे। I think it is very important to note that if we need to attract students from other parts of the world, if we need to attract foreign students, if you think students studying in India have done very well, —specially he was mentioning about Nepal and other countries where they are heading Governments —they should also

understand that if we need to attract the students from different parts of the world, we should try and give an atmosphere where there is no fear, where the students can come to our country, where there is law and order, where there is no social problem, where there is no mob lynching, where there is no lack of peace and order in the country. Only then the students from different parts of the world will be attracted to India. There are many speakers who gave so much of data about how there are no professors. But I would just like to mention here that in 12 of the 40 Central Universities, 75 per cent of the professors' positions are vacant and in two universities, one Central university of Haryana and the other Central university of Odisha, 100 per cent positions of professors are vacant. If you look at the declining rate of filling the faculty positions, in 2013-14, there were 1,25,338 professors who were working. From then to 2017-18, it has come down to 1,14170. That means about 14,000 professors' vacancies are not being filled up or the number of professors has come down. If you look at the figures for associate professors, in 2013-14, it was 1,82,681 professors who were working. In 2017-18 it was 1,39,000. There is so much of data which says that in the past five to six years, not enough attention has been given to higher education, no faculty positions have been filled, rules have been violated. There is so much interference by the Government in the universities, especially Central universities. They are trying to monitor other universities. They are trying to coach a university as to what the university has to do. I think, what is needed now is not the establishment of new universities, but what is needed now is to preserve the autonomy and independence of our universities. Only when we preserve the autonomy, there can be more creativity. More creativity will only help the nation to grow. There are so many other things. I would end by informing the House that there was one important news item today. It was a good piece of news. There is one, Mr. Ramgel Meena, a security guard at JNU, a first generation learner, has passed the entrance examination for admission to BA. He was supported by the students and teachers of JNU. I think, this is how a university should be.

With these observations, I support the Bill. Thank you.

श्री राजाराम (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरी पार्टी और मेरी पार्टी की नेता बहन कुमार मायावती जी इस बिल का समर्थन करती हैं। महोदय, बहुत से विद्वान साथियों ने इस बिल पर लम्बी चर्चा की है, इसलिए मुझे इस पर बहुत कुछ नहीं कहना है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से आंध्र प्रदेश राज्य में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का मार्ग भी सुगम और सुदृढ़ होगा। महोदय, ये जो दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुलेंगे, यह जो सरकार ने फैसला किया है, वह एक अच्छा कदम

[श्री राजाराम]

है, लेकिन मैं एक-दो बातें इस संबंध में अवश्य कहना चाहूंगा कि आज सच्चाई यह है कि जिस आदिवासी के विकास की बात हो रही है, जिस आदिवासी के नाम पर Central University बनाने की बात हो रही है, एक सच्चाई यह भी है कि वह जिस गांव से आता है, उस गांव में विद्यालय होता है, लेकिन वहां पर टीचर्स ही नहीं होते। अगर आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो वहां पर उन्हें शिक्षा मित्र कहा जाता है, अगर हरियाणा में चले जाएं तो guest teachers होते हैं, एमपी में चले जाएं तो अतिथि शिक्षक होते हैं - वहां से वह पढ़ाई करता है। अब आप सोचिए कि जब वह प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता है तो उसे पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं होते हैं और हम पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं कि वह इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस में आएगा, आईपीएस में आएगा। महोदय, एक सच्चाई यह भी है कि अगर सरकार की नीयत बहुत अच्छी है, सरकार को साफ नीयत के साथ अगर जनजातियों का विकास करना है, एसटीज़ का विकास करना है, आदिवासियों का विकास करना है तो उसे प्राथमिक शिक्षा के लिए भी अच्छे टीचर्स का प्रबंध और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। जब अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी, तभी वे केन्द्रीय विश्वविद्यालय में जाकर उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक-दो बातें सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं। क्योंकि मेरा समय बहुत कम है, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय में जनजातियों के लिए भर्ती या दाखिले में कोटा होता है? अगर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण देने का सरकार का इरादा है...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): अब समाप्त करें। इस पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय था, अब दो घंटे का समय over हो चुका है।

श्री राजाराम: मैं मात्र एक मिनट और लूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एससी, एसटी के लिए इस तरह का कोई प्लान है कि इन विश्वविद्यालयों में उनके दाखिले के लिए कोटा निर्धारित हो? इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि इससे आंध्र प्रदेश की कितनी एसटी की आबादी cover होगी? धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, Mr. Tiruchi Siva. Please restrict to your time. You have three minutes.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, the proposed amendment is to amend the Central Universities Act, 2009, to establish a Central University and a Central Tribal University in the State of Andhra Pradesh by fulfilling one of the obligations of the Andhra Pradesh Reorganisation Act.

Sir, it is to be welcomed and I support this Bill. Andhra Pradesh has so far no Central University. Sir, we assume, the Central University increases the access in quality of higher education. Many hon. Members have expressed their concern here, especially

those from Andhra Pradesh, and said that the total amount required is ₹ 870 crores. They also mentioned about the targeted time. They expressed apprehension whether it is possible to fulfill that since the amount allocated is not enough. I think, the hon. Minister will take care of it, because it should not stop with an assurance of setting up of university and creating infrastructure to impart education. My two important observations are these. A recent research has revealed –I think, it is not out of place to mention it here; it is very relevant because the hon. HRD Minister is here –that only 26 per cent of the passed-out engineering graduates are employable. So, by way of getting a degree, a person is not qualified to be employed. This is the state of affairs of our education. We are in a position to compete globally. And, of course, we aim at that. So, I would request the hon. Minister to concentrate on the quality of education, which is very important for the students. And, for that, some of the Members also raised their concerns about teachers. If the teachers are given importance only then they could impart to students what they actually need. Otherwise, we will just produce paper graduates. So, only the quality of education, if improved, will prove to be real symbol of higher education.

Now, I come to the Central Tribal University. I would like improving the knowledge and advancement of tribal art and culture by giving importance to the tribal population. It would, of course, teach other disciplines, like other Central Universities. But, I would like to know whether the admission to the Central Tribal University will be only for tribal students or for other students also. This is a very simple query. But, I wanted to know this because this university would be first of its kind. And, we welcome that. But, please clarify the ambiguity that has been created by the reasons given in the Statement of Objects and Reasons.

Third, I reiterate, in the earlier Bill passed with regard to reservation in the Central Universities, there were some exemptions to some universities with regard to reservation. My concern is, institutes of national importance and some research institutes already do not have reservation. And, there are some exceptions in the Central Universities also. I urge upon you that there has been a long history of how reservations were achieved to uplift the socially and educationally backward masses. So, I would urge upon you to kindly make reservations available in all the institutes of higher education. That would be a great gesture of giving importance to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and the Backward Classes.

I hope, much would come after this amendment and by way of establishing the Central University and the Central Tribal University. So, I welcome this Bill and support this. Thank you.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I welcome this Bill. I also welcome both the universities. I have great hopes that these universities will function as centres of inquisitive wisdom and knowledge; as centres of secular thoughts; as centres of freedom, peace, and fraternity; as centres of social justice and social progress; and, above all, as centres that will uphold scientific tempers. With this hope, I raise my voice in support of the propositions made by my comrades with regard to naming of these universities –one in the name of Rohith Vemula, and another in the name of Makhdoom Muhyadheen, the great Urdu poet and freedom fighter. These will be very simple gestures towards our great fighters.

Sir, today, I read a study report by the UNDP and Oxford Poverty and Human Poverty Index, which may be called multi-dimensional poverty index. It says that fifty per cent tribals of India are poor; thirty-three per cent dalits and thirty-three per cent Muslims are still poor. So, that should be at the centre of any attempt by the Government when it talks about equality in this country. And, when we talk about universities, those people who are deprived of human justice should be considered with all importance. So, I hope that the new universities will take these facts into serious consideration. Sir, I have a request to the hon. Minister to take note of. For the last six months, *dalit* students and students from minority sections are not getting their scholarships entitled to them, which is, Maulana Azad National Fellowship and Rajiv Gandhi National Fellowship. All over the country, they are knocking all the doors and they are waiting unendingly. I request you to personally look into the matter and see to it that their scholarships are released immediately. Sir, in the Bill, it is said that tribal universities will contemplate on tribal-centric higher education and research, including tribal art, culture and customs. I would like to add tribal rights, which are most important. All over the country, tribal rights are being snatched away. Those who are in power, those who are rich, those who speak a lot about development are snatching away the rights of tribal people. Their land is being snatched; their culture, their art, identity, everything is being snatched away by them. So, please see that their genuine rights are upheld.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude now. Your time is over.

SHRI BINOY VISWAM: With this request, Sir, I conclude. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Now, Mr. Minister to reply.

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': उपासभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि जो एक घंटे की चर्चा थी, वह दो में पहुंची और दो के बाद तीन में पहुंच गई है। माननीय पि. भट्टाचार्य जी ने चर्चा की शुरुआत की और श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव जी, श्री ए. विजयकुमार जी, श्री अबीर रंजन बिस्वास जी, श्री जावेद अली खान जी, श्री प्रशांत नन्दा जी, श्रीमती कहकशां परवीन जी, डा. के. केशव राव जी, श्री के.के. रागेश जी, प्रो. मनोज कुमार झा जी, श्री स्वपन दासगुप्ता जी, श्री वि. विजयसाई रेड्डी जी, डा. हनुमंतय्या जी, डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे जी, श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार जी, श्री प्रदीप टम्टा जी, श्री सुशील कुमार जी, श्री सैयद नासिर हुसैन जी, श्री राजाराम जी, श्री तिरुची शिवा जी और श्री बिनोय विश्वम जी ने चर्चा में भाग लिया। यह चर्चा श्री पि. भट्टाचार्य जी से शुरू हुई थी और श्री बिनोय विश्वम जी पर समाप्त हुई। श्रीमन्, मैं सभी सदस्यों का आभारी हूं। सभी सदस्यों के बहुत अच्छे विचार यहां पर आए। मुझे लगता है कि पूरे सदन को शिक्षा को लेकर काफी चिंता है। श्रीमन्, यह चिंता क्यों न हो? आखिर शिक्षा किसी व्यक्ति की, परिवार की, राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है। यदि किसी के शरीर की रीढ़ की हड्डी कमजोर होगी, तो अच्छा खास शरीर बेकार हो जाता है। इसलिए हमारी सरकार ने, श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने देश को भली प्रकार से समझा। श्रीमन्, किसी परिवार को, मसाज को, राष्ट्र को परिवर्तित करना हो, तो शिक्षा उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

उपसभापति महोदय, मैं देख रहा था कि नेल्सन मंडेला जी ने कहा कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार हैं। शिक्षा आदमी को उठाती भी है और गिराती भी है। जब आदमी उठेगा, तो परिवार उठेगा, समाज उठेगा, राष्ट्र उठेगा और व्यक्ति गिरेगा, तो परिवार गिरेगा, समाज गिरेगा, राष्ट्र गिरेगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था पहले से ही बहुत सुदृढ़ थी। पीछे के कालखंड की मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह सही है कि यह देश विश्व गुरु था, और आज हमारी सरकार आई, तो यह विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। श्रीमन् इसका रास्ता शुरू हो गया है। श्रीमन्, ली ग्रीन जी को इस बात को कहा कि जितना अधिक मैं जीता हूं, उतना अधिक मैं सीखता हूं और जितना अधिक मैं सीखता हूं, उतन अधिक अहसास होता है कि मैं बहुत कम जानता हूं। श्रीमन्, जीवनपर्यन्त शिक्षा का सीखना, नई-नई जानकारियां हासिल करना और उसे अपने जीवन में उतारना स्वाभाविक है। यह भी स्वाभाविक है कि आदमी की जींवतता तभी बनी रहती है, अन्यथा वह हाड़मांस का एक ढांचा बन कर रह जाएगा।

श्रीमन्, यदि आपकी इजाज़त हो, तो मैं जितने माननीय सदस्यों ने यहां बोला है, उनके द्वारा बोले गए एक-एक बिन्दु पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे कम-से-कम दो से ढाई घंटे की जरूरत पड़ेगी। यदि यह सदन इस बात से सहमत हो, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: हाउस की sense ले लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ...**(व्यवधान)**... इसमें दो बातें हैं। जो विचार आए, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं, जो नए हैं और उन्हें करने की जरूरत है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं, जिन्हें गवर्नमेंट कर रही है। परन्तु मेरी चिन्ता का विषय दूसरा है, क्योंकि यह उच्च सदन है। यदि पिछले पांच वर्ष का कार्यकाल देखा जाए, तो गवर्नमेंट ने इस कालखंड में जो किया, वह शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। इसलिए इन पांच वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो किया है, उसकी जानकारी सभी माननीय सदस्यों को जरूरी होनी चाहिए, यह मेरा विचार है। ...**(व्यवधान)**...

डा. के. केशव राव: इस विषय पर अलग से डिबेट होनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': हां, जरूरी होनी चाहिए। श्रीमन्, शिक्षा पर तो खूब होनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

डा. के. केशव राव: सर, आज के लिए तो let them concentrate and give reply on the Bill, facts of the Bill. हमने बिल के ऊपर जो objections किए हैं और जो suggestions दिए हैं, उनके बारे में बता दीजिए।...**(व्यवधान)**...

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': आप केवल बिल पर कहना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि देश के इतिहास में, देश की आजादी के बाद, बहुत सारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, यदि इतने कम समय में एक सीमा तक शिक्षा संस्थानों की स्वीकृति और क्रियान्वयन हुआ, तो वह केवल हमारी सरकार में हुआ और कहीं नहीं हुआ।

श्रीमन्, मेरे राज्य का भी पुनर्गठन कुछ वर्ष पूर्व हुआ। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please, Keshava Raoji. ...*(Interruptions)*... Only Hon. Minister's reply will go on record. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Mr. Minister, you address the Chair. ...*(Interruptions)*... Please, Keshava Raoji. ...*(Interruptions)*... You address the Chair. ...*(Interruptions)*... प्लीज़, प्लीज़। कृपया बोलने दें। मंत्री जी को बोलने दें। ...**(व्यवधान)**... आप कृपया वहां बैठकर टिप्पणी न करें। ...**(व्यवधान)**...

DR. K. KESHAVA RAO: *

उपसभापति: माननीय के. केशव राव जी, प्लीज़, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए, मंत्री जी को बोलने दें। ...**(व्यवधान)**...

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, मैंने सभी माननीय सदस्यों को बहुत शांत भाव से सुना। इसलिए मैं यह अनुरोध जरूर करूंगा कि मुझे भी शांत भाव से सुना जाए। यदि किसी को कोई दिक्कत होगी, तो हम मिलते भी हैं और यहां से बाहर जाकर भी मिलेंगे। जब यह बात हो गई कि ठीक है, मैं विस्तार नहीं करूंगा और मैं उन बिन्दुओं पर न जाऊं, बल्कि केवल एक्ट पर

*Not Recorded.

आऊं, केवल विश्वविद्यालय के ऊपर ही बात करूंगा, तो मैं उसी पर तो आ रहा हूं। इसीलिए तो मैंने कहा कि इतने कम समय में, मैं आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट, 2014 की बात कर रहा हूं और मैं भी केवल वर्ष 2014 की बात कर रहा हूं कि वर्ष 2014 के बाद, इन पांच सालों में जो हुआ, वह इतिहास में कहीं भी और कभी भी नहीं हो सका। यह बात मैं प्रमाण और तथ्यों के साथ कह सकता हूं। ...**(व्यवधान)**... श्रीमन्, मैं अभी तो सरकार के बारे में बता रहा हूं। मैं इनके बारे में भी बोल सकता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मंत्री जी, आप कृपया सिर्फ चेयर को ही संबोधित करके अपनी बात कहें।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': मैं इसलिए यह कहा हूं कि इन पांच सालों में क्या इन्हें मालूम नहीं कि IIT की स्थापना हो गई, क्या मालूम नहीं कि NIT की स्थापना की गई, क्या मालूम नहीं कि IM की स्थापना हो गई। क्या मालूम है कि ISER की स्थापना हो गई, क्या मालूम है कि IIIT की स्थापना हो गई। आज आंध्र प्रदेश का सपना पूरा हो रहा है और वहां दो विश्वविद्यालय और खोले जा रहे हैं। इसलिए मैं आंध्र प्रदेश को और उसकी जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूं।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि इए एक्ट से संबंधित कुछ दो-तीन चिन्ताएं विशेषकर लगीं, उनके बारे में बताना चाहता हूं। एक तो कुछ लोगों के मन में यह है कि नहीं, केवल इतना ही पैसा स्वीकृत है और बाकी कब होगा और दूसरी चिन्ता कुछ लोगों ने यह दिखाई कि वह कब पूरा होगा? कुछ सदस्यों ने कहा कि अभी तो मंत्री जी ने कहा कि पहले चरण में इतना है और इसके पता नहीं कितने चरण होते हैं, कुछ सदस्यों की यह आशंका थी कि केवल 420 करोड़, या जो प्रावधान है, उसके अनुसार 485 करोड़ मिलेंगे क्या? मनोज जी अभी यहां पर नहीं हैं, उन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की थी कि 420 करोड़ की जगह 419 या 421 करोड़ हो जाएं। मैं कहना चाहता हूं कि हमने उनकी चिंता को पहले ही हल कर दिया है। सर, ये पचास लाख पहले ही ऐड कर दिए हैं। हमने इसको 420.50 करोड़ कर दिया है। मुझे चिंता यह हो रही थी कि उनका नंबर दसवें पर था, यदि यहीं खत्म हो जाता, तो उनको वह भी चिंता होती, लेकिन यह 20 तक गया है।

श्रीमान्, केंद्रीय विश्वविद्यालय में 420 करोड़...**(व्यवधान)**...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): हमने 420 करोड़ मंजूर कर दिए हैं।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': सर, 902.07 करोड़...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अठावले: हमने यह किया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अठावले जी, आप कृपा करके बैठिए। आप बोलिए।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमान्, जहां तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का विषय है, ये जो 902.07 करोड़ हैं, इसके जो प्रावधान हैं, जो स्वीकृत हैं, हम उसके पहले चरण में 450 करोड़ रुपये जारी कर रहे हैं। जो केंद्रीय जनजाति वाला विषय है, उसके लिए टोटल प्रावधान 834.83 करोड़ रुपये का है और हम इसके पहले चरण के लिए 420 करोड़ रुपये जारी कर रहे हैं। हम इस समय इस एक्ट के साथ 870 करोड़ रुपये ला रहे हैं। माननीय सदस्य की जो दूसरी चिंता थी, वह यह थी और जो आपने कहा कि पहले चरण में - सर, क्योंकि यह बिल अभी पास नहीं हुआ था, आज सबकी सहमति से यह बिल पास होगा। यह विश्वविद्यालय, जिसके लिए 1736.90 करोड़ रुपये हैं, इसके लिए यह सुनिश्चित है कि यह चार सालों में पूरा किया जाएगा। इसको चार वर्ष के अंदर-अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। हम इसके लिए एक-एक महीने और एक-एक दिन का प्रावधान कर रहे हैं।

श्रीमन्, जो दूसरी बात विशेषकर आई, वह यह थी कि इसमें विलंब क्यों हुआ? इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें बारी-बारी से विलंब होता है। जब हमारा "उत्तर प्रदेश पुनर्गठन एक्ट, 2000" आया था, तब मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री था और आज, 19 वर्षों के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिनको हम उत्तराखंड में शुरू नहीं कर पाए। यह किसी भी राज्य के लिए हो सकता है। मैंने सभी राज्यों के पुनर्गठन एक्ट को पढ़ा है और देखा है। मुझे यह भी मालूम है उसके बाद उनकी सम्पत्तियों पर कब्जा करके क्या निर्णय लिए गए। यदि आप मौका देंगे, तो मैं इसके एक-एक बिन्दु के बारे में बता दूंगा। मैंने इसलिए कहा कि देश की आज़ादी के बाद इतने कम समय के अंदर, इस सीमा तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर को छूने वाले ये वे संस्थान हैं, जिनकी इतनी जल्दी स्वीकृति हुई है। क्या सभी लोगों को हमारी सरकार को इसके लिए बधाई नहीं देनी चाहिए? ...**(व्यवधान)**... यदि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, तो कम-से-कम शिक्षा के लिए यहां से बधाई देनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा तो यहां से है। हां, हमारे माननीय सदस्य को तेलंगाना की चिंता है।

उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं इन दोनों की स्वीकृति दे रहा हूं, लेकिन मैं विरोध भी कर रहा हूं, वह मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन वह विरोध भी नहीं था, उनका थोड़ा-सा यह जरूर कहना था कि जो "तेलंगाना पुनर्गठन एक्ट, 2014" है, उसमें तेलंगाना भी एक विषय है और तेलंगाना के लिए भी एक जनजातीय विश्वविद्यालय का प्रावधान है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम हर हालत में, बहुत जल्दी तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय शुरू करेंगे। हम उसका रास्ता तय कर रहे हैं। हमने लगातार कोशिश की है, पर हमें जमीन नहीं मिली है। मैं इस बात को कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इसका तिथि-वार आकलन है। मुझे मालूम था कि कुछ सदस्य इस बात को लेकर प्रश्न करेंगे, इसलिए मेरे पास इसका तिथि-वार एक-एक आकलन है कि हमने स्टेट गवर्नमेंट को कब और कितने पत्राचार किए। यदि एक स्थान नहीं था, तो हम दूसरे पर गए, दूसरा नहीं था तो तीसरे पर गए, तीसरा नहीं था, तो अन्य पर गए, अंततोगत्वा यह बनेगा तो जमीन पर ही, आसमान पर तो बनेगा नहीं। आप यह समझ लीजिए कि जमीन गवर्नमेंट को देनी होगी। जिस दिन तेलंगाना वाली जमीन हमारी पहुंच में हो जाएगी, उस दिन यह तेलंगाना में जल्दी से जल्दी पूरे तरीके से बन जाएगा।...**(व्यवधान)**...

श्रीमान्, बहुत सारी चीजें हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 32 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति आ रही है। हमारे प्रधान मंत्री जी का मानना है कि नहीं, दुनिया इतनी दूर जा रही है। अभी इस सदन में यह भी चिंता की गई, हमारे एक सदस्य, शायद राकेश जी ने इस बात को कहा। मैं इसको अलग से नहीं देख पाया, लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि हम पूरी दुनिया के शिखर पर जा रहें हैं। श्रीमन्, हम 5 वर्ष पहले भविष्य की रैंकिंग में नहीं थे, लेकिन आज मुझे खुशी से इस बात से इस सदन को अवगत कराना पड़ रहा है कि हमारी IIT, Bombay; IIT, Delhi और IISc, Banglore रैंकिंग में 200 के अंदर आकर शिखर को चूम रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इस समय 500 के अन्दर 9 संस्थान हैं और 1,000 के अन्दर 23 संस्थान हैं।

श्रीमन्, हमारे प्रधान मंत्री जी ने HEFA के अन्दर इनकी स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए तमाम संस्थानों को सहायता सुनिश्चित की है और इनके लिए एक लाख करोड़ का अलग प्रावधान किया है। अभी यहां बजट के बारे में कहा जा रहा था। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बजट कम नहीं हुआ है, आप देखिए, आपने बजट को देखा क्यों नहीं? यह 2013-14 में 66 हजार करोड़ होता था और आज यह 95 हजार करोड़ हो गया है। इसमें पिछले वर्ष से भी 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। यह कम हो रहा है या ज्यादा! इतना ही नहीं, ...**(व्यवधान)**... जो 95 हजार करोड़ है ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seats. ...*(Interruptions)*...

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': इसमें गत वर्ष से भी 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, कृपया आप चेयर को सम्बोधित करके बात करें।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, जो गत वर्ष का बजट है, उससे भी 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। जो बजट के प्रावधान से नहीं जाता, जो हम HEFA के तहत दे रहे हैं, यदि मैं उस 30 हजार करोड़ को भी इसमें लगाऊंगा, तो यह 1 लाख 25 हजार करोड़ का प्रावधान है। श्रीमन्, हम सोच भी नहीं सकते, 2013-14 के बाद यह just double हो गया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बजट के प्रावधान में कहीं कमी आई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र में काम किया है, वह बहुत तेजी से हो रहा है, वह चाहे बजट का प्रावधान हो, चाहे प्रतिष्ठापूर्ण संस्थानों की स्थापना का विषय हो; जो विश्व की रैंकिंग में तेजी से दौड़ेंगे, बढ़ेंगे।

श्रीमन्, पहले तो मैं नरसिंहा राव जी और सहस्त्रबुद्धे जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस बात को कहा - ' Study in India' 'भारत में जानें, समझें, आएं, भारत को देखें', इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। इसमें लगभग 70 हजार लोगों का पंजीकरण हो गया है। जिस तरीके से हमारे प्रधान मंत्री जी ने पूरे विश्व में FDI के क्षेत्र में देश को नम्बर एक देश बनाया, निवेश के क्षेत्र में हमारा देश नंबर एक देश बना है, उसी तरह हम नवाचार के क्षेत्र में भी इसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा hub बनाएंगे। इस दिशा में काम होना शुरू हो गया है।

[श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक']

श्रीमन्, अभी शैक्षणिक गुणवत्ता और नई शिक्षा नीति की बात कही गई। इस सम्बन्ध में मेरा जरूरी अनुरोध रहेगा कि हमने नई शिक्षा नीति को लेकर पिछले 3 वर्षों में लगातार हर स्तर पर चर्चा की है। हम 1 लाख 10 हजार ग्राम समितियों तक गए हैं। चाहे विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, शिक्षक हो, अध्यापक हो, वैज्ञानिक हो, समाज का व्यक्ति हो, छात्र हो, छात्राएं हों, यहां तक कि 10 समितियों में वैज्ञानिक से लेकर विशेषज्ञों की समिति ने उसमें योगदान दिया। श्रीमन्, हमने इस नई शिक्षा नीति का मसौदा public domain में डाला हुआ है। बहुत सारे लोगों की यह शंका है कि वह नई शिक्षा नीति क्या है और कुछ लोगों ने कहा है कि आप इसको भी डालिए, उसको भी डालिए, तो मेरा बहुत विनम्र अनुरोध होगा कि अभी वह public domain में है, मेरा सबसे बहुत विनम्रता से अनुरोध होगा कि उसको जरूर देखें, जरूर पढ़ें और जितने भी सुझाव हों, आप उसमें अपने सुझाव दें, ताकि हम उसको और सुदृढ़ बना सकें और इस राष्ट्र की नींव को और मजबूत बना सकें, जिससे हम सारे विश्व में फिर इस देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकें। चाहे नवोन्मेष के रूप में हो, चाहे उच्च शिक्षा आयोग बनाने की दिशा में हो, हम हर क्षेत्र में बहुत आगे चल रहे हैं।

श्रीमन्, इस बिल से सम्बन्धित विशेषकर मुझे यही कहना था कि हम जो जनजातीय विश्वविद्यालय ला रहे हैं, वह केवल उसी क्षेत्र के लिए नहीं होगा। हां, जो अभी प्रदीप भाई और बहुत सारे लोगों ने कहा कि दोनों में क्या अंतर होगा, तो इसमें बहुत साफ अंतर है कि मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा में अनुसंधान सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हम इसे लाए हैं। आदिवासी कला, संस्कृति, परंपरा, जनजातीय क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी में भाषा, चिकित्सा प्रणाली, सीमा शुल्क, वन आधारित आर्थिक गतिविधियां, वनस्पतियां, जीव जंतु, टेक्नोलॉजी की उन्नति, अनुसंधान, ये सभी इसमें समाहित हैं। इसलिए अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय में जो चीज़ें हैं, वे सभी कुछ होने के बावजूद भी इस विश्वविद्यालय में कुछ विशेष भी होगा, यह बहुत स्पष्ट है। श्रीमन्, अभी बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अलग से होने चाहिए, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय तो अलग से ही हैं, तभी तो आज और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की मांग हो रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय कहीं न कहीं, किसी न किसी दिशा में पहले से ही स्थापित हैं।

श्रीमन्, अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि सदन के सभी सदस्यों ने इस बिल के बारे में बहुत अच्छा बोला है। सभी माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पास किया जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is that the Central Universities (Amendment) Bill, 2019 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. ...*(Interruptions)*...

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, I am asking him a question. ...*(Interruptions)*...I am not criticising. ...*(Interruptions)*... We support the Bill with full heart. Mr. Minister, you have brought the Bill when there is already a University, please understand this. The Andhra Central University is functioning for the last two years. This Bill has come today. We thought last time you could not do it in the Lok Sabha, you have done it now. There has to be one clause in this Bill saying that it will have retrospective effect. Otherwise, the students would not get the degrees. That is what I am asking.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Keshava Rao*ji*. Now, the question is... ...*(Interruptions)*...

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, will the Minister not respond? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill further to amend the Central Universities Act, 2009, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there are two Amendments (Nos. 1 and 2) by Dr. T. Subbarami Reddy.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, before I consider my decision to move my Amendments, I just wish to say that through my Amendments, I seek to enlarge the scope of University by including research and innovative technology facilities for the tribal and primitive tribal population of India. This is just to bring to the notice of the Minister. I am not moving my Amendments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Subbarami Reddy*ji*. Amendments not moved.

Clause 2 was added to the Bill.

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Minister to move that the Bill be passed.

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.